(SHRI HANS RAJ BHARDWAJ): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Contract Act, 1872.

The question was put and the motion was introduced.

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Madam, I introduce the Bill.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS—Contd.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Babul Reddy—Not here. Shri Darbara Singh.

श्री दरबारा सिंह (पंजाब) : उपसभापति महोदया, सबसे पहले मेरे सामने कोई है ही नहीं जिसको मैं बातें सुना सकूं ।

श्री मिर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : रास्ता साफ है ।

श्री दरबारा सिंह : मुझे रास्ता साफ नहीं चाहिये । हमारे सामने प्रेजीडेंट आफ इण्डिया ने जो एड्रेस दिया है उसकी सबसे बड़ी अहमियत इस बात की है कि उन्होंने साफ तौर पर आज की पोजीशन जो है उसको जाहिर किया है बिला इस लिहाज के कि वह किस को भाती है, किस को ठीक नहीं लगती है । सबसे ज्यादा जो हमारे देश में हम सब पर असर हुआ है वह सूखे का असर हुआ है खुशकसाली का असर हुआ है । इस सूखे की भयंकर समस्या से निपटने के लिए इस सरकार ने जो कुछ किया है वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमने कभी भी ऐसा सूखा नहीं देखा और इतने अधिक लोगों पर इस सूखे का असर हुआ है चाहे वह राजस्थान के लोग हों या गुजरात के हों या किसी दूसरे सूबे के हों । सबसे ज्यादा सूखे की वजह से नुकसान हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि एक भी आदमी इस सूखे के कारण अन्न की कमी की वजह से मरा नहीं है । ठीक है, हमारे हालात खराब हुए हैं बहुत सा रुपया जो लोगों की दूसरी बेहतरी के लिए काम आ सकता था वह लोगों को खुराक पहुंचाने के लिए लग गया इसलिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि एक भी आदमी खुराक की वजह से मरा नहीं है । अपनी लाइफ टाईम की जिन्दगी में किसी की मौत हो गई हो लेकिन खुराक न मिलने की वजह से कोई नहीं मरा । तो इस सूखे की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जो इतना अच्छा काम किया है मैं समझता हूं इतना बड़ा सूखा पहले कभी नहीं हुआ और गवर्नमेंट ने भी इतनी बड़ी मदद की है । मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि हमें यह समझना चाहिये कि यह देश बहुत बड़ा है और इस देश में जितना रुपया इस बात के लिए खर्च किया गया है वह रुपया दूसरे डवलपमेंट के कामों के लिए काम आ सकता था । मैं एक तजवीज देना चाहता हूं । यह मुश्किल हमेशा न बनी रहे, कभी हमारे यहां बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, मेरा सुझाव यह है कि इसके लिए एक स्थायी बन्दोबस्त करने की जरूरत है और इसके लिए जितने भी हमारे देश में दरिया है उनके लिए एक हमें गारलैंड कैनाल बनानी चाहिये जहां ज्यादा पानी है वहां से उस क्षेत्र में पानी भेजा जा सके जहां पर पानी नहीं मिल रहा है । लेकिन यह बड़ी लम्बी स्कीम है । लेकिन इस स्कीम को चालू करने की जरूरत है । जरूरत इसलिए है कि हर साल हम जो ड्राउट पर, फ्लड्स पर पैसा खर्च करते हैं क्यों न हम तजवीज करें कि वह पैसा लगातार खर्च किया जाता रहे इस बात के लिए कि हमारे सारे दरियाओं को इकठ्ठा करके उनका एक ऐसा कैनाल सिस्टम बना दें कि जहां जरूरत पड़े वहां पानी जाये, जहां जरूरत नहीं है वहां से निकालकर दूसरी तरफ भेजा जा सके । यह एक बहुत लम्बी स्कीम है जो हमारे पिछले इरीगेशन के मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी तजवीज बनायी थी । इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ।

मुझे एक और चीज की भी खेद है । परेशानी इस बात की है कि हिंदुस्तान में जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज हैं जो इसको तोड़ना चाहती है वे कहीं न कहीं किसी न किसी जगह सिर उठा रही है । यही नहीं वे रीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर या सूबे के नाम पर किसी न किसी तरह से ऐसी बातें आगे बढ़ा रही हैं कि जिससे

हमें मालूम पड़ता है कि ये ताकतें किसी न किसी शह पर, बाहर की शह पर या अंदर की शह पर पैसे के लिए इस तरह की कई चीजें आगे बढ़ा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर एक हमारे यहां से जो निकल गये उन्होंने जो कहा है वह कितनी डिस्ट्रक्टिव बात है। यह बात मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि रिफरेंडम श्रीलंका में करवाया है हिन्दुस्तान की सरकार ने, अब यह रिफरेंडम श्रीनगर में हो जाये तो क्या होगा। मेरा मतलब यह है कि उनको भड़काने के लिए, उनको शह देने के लिए यह है। क्या यह कोई नेशनल आउटलूक है, नहीं बल्कि यह एण्टी नेशनल आउटलूक उन लोगों का है जो ऐसी बातें बढ़ा रहे हैं, हमें दिखाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्राइममिनिस्टर को कहते थे कि हम वफादार हैं। वह हमारा लीडर है और इसके साथ यह कहते थे कि हम कांग्रेस में रहेंगे कहीं नहीं जायेंगे। अब न कांग्रेस में हैं, न उनके लीडर हैं, न खुद किसी के लीडर हैं। कन्फ्यूजन में सारी बातें कहते हैं। हिन्दुस्तान की जो हालत है व्यवस्था है उसको आगे दुरुस्त करने की बजाये निगेटिव प्रोग्राम सारे के सारे दे रहे हैं। उनके साथी भी ऐसे हैं लोगों को कहते हैं बहुत करप्शन है। मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, कौन सा सेल खेला जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में क्या कुछ नहीं हुआ। जजेज ने फैसले किये हैं, जजमेंट्स आ रहे हैं उनको कैसे विशिएट किया जा रहा है बजाये इसके कि आगे चलें।

मैं समझता हूं कि ऐसी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जिनसे खबरदार रहने की जरूरत है। बाहर की ताकतें भी जोर लगा रही हैं? मैं कम्युनलिज्म के बारे में भी में अर्ज करना चाहता हूं। कम्युनलिज्म ऐसी बीमारी है जिसका इस्तेमाल लोग सियासी ताकत हासिल करने के लिए करते हैं। मैं पिछली बहुत दफा कह चुका हूं और वचनबद्ध हूं इस बात के लिए कि पोलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग करने की जरूरत है। अगर यह नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्राब्लम होगी। हमारी बहुत बड़ी प्राब्लम यह भी है कि हम देखते है कि किसी न किसी गुरुद्वारे से, मन्दिर से मस्जिद से आवाजें उठती हैं कि हम वे नहीं हैं, हमारे फिरके पर अटैक हो रहा है। हम एक अलहिदा कौम हैं। सौ सौ बातें कहते हैं। वहां से जो जो बातें कही जाती हैं उनका अर्थ यही है कि हिन्दुस्तान को कैसे तोड़ा जा सकता है, हमारी कम्युनिटी कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कैसे दूसरे पर डामिनेट कर सकती है और कैसे सियासी ताकत हासिल कर सकती है। इसीलिए सारा जोर लगाए हुए हैं।

प्रेजीडेंट एड्रेस में पंजाब के बारे में जिक्र आया, मैं उस पर भी कहना चाहता हूं कि यह आसान बात नहीं है। मुश्किल हालातों में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स उसकी पूरी तरह से देखरेख कर रहे हैं। यह ठीक है कि इसका सियासी मसला हल करने की जरूरत है लेकिन वहां जो ताकत है अकालीदल यह कहती है--मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बताऊंगा--बाहर की दुनिया में इंटरनेशनल तौर पर कि हमारे खिलाफ टेरोरिज्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। यह भी अलहिदा बात है, मैं कहना चाहता हूं कि जो ताकत अपने आपको दल कहती है यह दो हिस्सों में तकसीम है। ये कहते हैं हमको सरकार दो। अब सरकार किसको दें यह उनको खुद पता नहीं लगता है। यह उनको खुद पता नहीं लगता कि सरकार किसने बनानी है किसने नही बतानी है। वे यह कहते हैं कि जो सिख हरियाणा में रहने वाले हैं उनको चाहिए कि वे देवीलाल जी की मदद करें। किस बात के लिए? बतायें तो सही। अब जो खुद के उन्होंने झगड़े डाले हुए हैं वे हम पर थोपते हैं। लुधियाना में उन्होंने को कांफ्रेंस की है उसमें टेरोरिज्म के खिलाफ एक बात नहीं उठाई, एक अल्फाज नहीं उठाया, एक भी बात नहीं कही कि टेरोरिज्म बुरा है, टेरोरिज्म क्यों है जो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे। छोड़िए उनका मुकाबला करने की बात उनकी जुबान से यह नहीं

[श्री सरदारा सिंह]

निकलता, आज सरदार बादल से पूछा गया। जरा बताइये तो सही कि यह टेरोरिस्ट जो बेगुनाहों को मारते हैं आप उनके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते ?

वह कहते हैं कि हमें क्या पता है कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। यह पता नहीं, जिस गरीब के ऊपर जो अपनी दुकान में बैठा हुआ है, उस पर गोली चलाई जाती है, जिस राह चलते-चलते पर ए० के०-47 द्वारा गोली मार दी जाती है, वह पता नहीं कौन हैं ! मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए, हर मुल्क से हमारी दोस्ती होनी चाहिए मैं मानता हूं, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है--कितने ट्रेन करके लोगों को यहां भेजा--जितने टेरोरिस्ट पकड़े जाते हैं, वह अपनी जबान से कहते हैं कि हमें फलां जगह पर रख कर ट्रेनिंग दी गई, आर्म्स दिये गये पैसा दिया गया ताकि हिंदुस्तान की डी-स्टेबेलाइजेशन हो सके। मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं—जो प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं, उनको छोड़िए जो बाकी हैं, कभी इनकी जबान से यह निकला है। एक पार्टी तो यह कह रही है कि वह ठीक कर रहे हैं, कि वहां मसले को हल जान-बूझ कर नहीं किया जाता।

प्राइम मिनिस्टर ने वाजे तौर पर कहा कि है हमारी इंटेंशंस क्लियर हैं, हम चाहते हैं कि यह मसला पंजाब का हल हो, लेकिन हल करने के लए कोई आगे बढ़े जो भी आना चाहता हैं हमसे बात करे। यह बार-बार उन्होंने कहा है, लेकिन कहते हैं कि हम नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे, तो मसले हल कैसे होंगे ? मैं तो उनसे बार-बार यही कहता रहा हूं कि जाइये प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, इसको हल करने के लए अपनी तदबीज दीजए लेकिन कसी मे जेस्ट्रेट फैसला करने के लिए यह कहा जाए कि आपकी बातें तो हम मान लेंगे, आपका फैसला न लेंगे अगर मेरे हक में वह करते हैं। यह कौन सी बात है, और कहां का इंसाफ है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग जो आज हम देखते हैं कि वहां बहुत बड़े-बड़े आदमी हैं और कहते है कि हमें सारी ताकत दे दो, वह सारे के सारे ही उन लोगों की मदद कर रहे हैं, डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली जो टेरोरिस्ट्स है। मैं आपको वाजे तौर पर कहना चाहता हूं कि यह कहां-कहां इंटरनेशनल तौर पर हैं।

ब्रिटेन अमरीका और वेस्ट जर्मनी में कंस्पीरेसी यह है कि टेरोरिस्ट्स को वहा से मनी भी मिलती है आर्म्स भी मिलते हैं ट्रेनिंग भी मिलती है और आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमरीका वालों ने कहा हैं कि टेरोरिस्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए हमें हर किसी को इजाजत है यह इल्लीगल नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि आप टेरोरिस्टस को अपने लिये बनाइये, लेकिन वह तैयार करके हिंदुस्तान में न भेजें। वह हिंदुस्तान की वहा त को खत्म करने के लिए जो कर रहे है, पाकिस्ता ी तरफ से कार्य कर रहे हैं, आप इनकी इमदाद मत की जए। तो इससे पता चलता है, एक एजेंसी आई० ए० एन० एस० है, उसने एक तेजिन्द्र सिंह पुरोही, जो लाहौर में दस महीने जेल में भी रहा है, वहां से उन्होंने कहा कि साऊथ अमरीका से तेरह करोड़ रुपया इसको भेजा हैं, और इसलिए वहां जो मुकदमें चल रहे हैं उसके लिए वैनकवर में भी दो करोड़ से ज्यादा डालर जो है वह उसको छुड़वाने के लिए खर्च किया है। तो, कौन-कौन सी बात कहें।

ऐसे और भी केसज हैं, जिनमें मैं साबित कर सकता हूं कि वहां से जो पैसा आता है, वह डी-स्टेबिलाइजेशन के लिए ही आता है। मैं उन बातों में नहीं पड़ना चाहता हूं जो मैं पीछे कह चुका हूं। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान को मदद मिल रही है, वह मदद आज अफगानिस्तान के साथ— प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिया आयें और आकर

के बात करें अफगानिस्तान के बारे में, लेकिन उसने इनकार किया । किस बात के लिए ? क्योंकि उसके पीछे ताकत है। आज अमरीका बेशक ओपनली यही कहता हो कि सुलाह-सफाई हो जानी चाहिए ।

आज तो रूस वालों ने एक और बात भी कही है कि फलां जगह से, चेकोस्लोविया से भी हम बड़े हथियारों को एक हफ्ते में शिफ्ट कर देंगे । वह इनिशिएटिव जो है, वह क्यों नहीं लेता, बजाए इसके कि वह अफगानिस्तान में, पाकिस्तान को तैयार करके अफगानिस्तान में गड़बड़ पैदा करने के लिए कायम रहे और हिंदुस्तान की वहादत को तोड़ने के लिए भी सारी कोशिश जो है-- अगर उनको पैसा न दिया जाए, तो पाकिस्तान जो है, वह नीचे आएगा बात करेगा अपनी इकानमी को दुरुस्त करने के लिए, जिनसे वह लड़ रहा है, उनसे बात करने की कोशश करेगा, हम यह चाहते हैं कि वह ऐसी बात न करे और जो हो रहा है, इंटेरिम गवर्नमेंट उनकी मरजी की बन जाए और रिबेल्ज उनको जाकर कंट्रोल कर ले, कौन ऐसी इजाजत देगा । यह रास्ते में रुकावट डालने के लिए है, जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान वाले कोशिश करते थे ।

मैं प्राइम मिनिस्टर को इस बात के लिए मबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि इस रीजन में अमनोअमान कायम करने के लिए निहायत जरुरी है कि अफगानिस्तान का मसला भी अच्छी तरह से तय हो सके, लेकिन लोगों ने कहा है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या है और फिर यह कहते हैं कि आप वहां क्या कर रहे है । यह लोग कहते हैं कि श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वह गलत किया जा रहा है । आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कुछ दिनों में ही, कुछ घंटों में नहीं, 48 घंटे दिये हैं उनको कि वे अपने हथियार छोड़कर आयें और जो भी "लट" का आदमी है लीडर है उसने यह कहा है कि हम आने के लिये तैयार हैं, हम बात करने के लिये तैयार है और यह झगड़ा खत्म करने के लिये तैयार हैं । यह अगर इस बात का बुरा समझते हैं तो आप मद्रास में जाकर देखिये कि कौन सी पार्टी है । खुद कह रहे है और खुद सवाल उठा रहे है । वह लोग यहां से जाकर वहां कहते हैं कि नहीं कोई समझौता नहीं होना चाहिये था । हिन्दुस्तान को इसमें नहीं पड़ना चाहिये था । वह फौज को उभारते हैं । कभी किसी को उभार देते हैं और कभी किसी को और यह उभार बहुत खतरनाक हालात में जा रहे हैं । इसलिये मैं आपकी मार्फत अपील करना चाहता हूं कि जो आपोजीशन में बैठे हैं कि आइये और इस मसले को हल करिये, न कि इसको उभारने के लिये कुछ करें । तो मैं अर्ज कर रहा था यह अगर पिछली बार होम मिनिस्टर ने यहां कहा था कि हम कोई कानून का ड्राफ्ट ला रहे है जिसमें पोलिटिक्स और रिलीजन को अलग करेंगे । मैं चाहता हूं कि इसको अगर करेंगे तो 50 परसेंट से ऊपर आपकी प्राब्लम दूर हो जायेंगी क्योंकि आज हिन्दुस्तान में इसी नाम पर ही उभार दिया जाता है और लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है । यह कहते हैं कि हमारा मजहब खतरे में हैं । जो नेशन की परिभाषा है, वे अपनी कम्युनिटी के आधार पर अपने आपको नेशन कहते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान एक ही नेशन है । इस मैं बार-बार कहता हूं और कहता चला जाउंगा कि हिन्दुस्तान एक ही नेशन है और उस नेशन का नाम ही हिन्दुस्तान है । हिंदुस्तान के अन्दर जो कम्युनिटीज हैं वे अपने आपको नेशन नहीं कह सकती । मजहब के आधार पर, फिरके के आधार पर बने हुये जो गठबन्धन है वे अपने को कम्युनिटी ही कह सकती है वे नेशन नहीं बन सकतीं । इसलिये हिन्दुस्तान एक नेशन है और उसमें हिन्दू, सिख, पारसी, इसाई कोई भी हो सब मिलकर एक नेशन बनाते हैं और इसी आधार पर सारी बात आगे बढ़नी चाहिये । हमारी मुखालफत करने हैं तो करते जायें डेमोक्रेसी में इसकी हर किसी को इजाजत है लेकिन यदि कोई इस देश को तोड़ने की कोशिश करे तो इसकी किसी को इजाजत नहीं है ।

[श्री दरबारा सिंह]

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसके लिये यह रीजनल पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसके लिये बात-चीत की जा रही हैं कि कैसे इस को कन्ट्रोल एर सकते हैं। वह एक सज्जन को यहां से हटकर गए हैं फाइनांस मिनिस्टर वह यह बात कर रहे हैं कि बी०जे०पी० को कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव आदमियों से मिले हुये हैं लेकिन कैसे उनके खिलाफ बोलें। अगर आप समझते कि हैं कम्युनल पार्टी है तो फिर उसके खिलाफ बोलिए बी०जे० पी० के खिलाफ बोलिए। बोलने की बजाय अन्दर से गठजोड़ कर रहे हैं ताकि हिन्दुस्तान को तोड़ा जाए और प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए। यह प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बात करते है। क्यों 5 साल के लिए लोगों ने उन को ताकत दी हैं आपने ताकत नहीं। देहात के लोगों ने किस बात के लोगों ने एक-एक वोटर ने वोट डालकर हमे यहां पर लाया है। पांच साल के बाद इलैक्शन होंगे फिर देखेंगे कि कौन आता है और कौन जाता है। अब इसके लिए यह पांच साल से पहले ही सवाल उटाते हैं कि अभी हटाओं। देश में करप्शन बहुत है। अब आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में क्या हाल है। उसके बारे में आज भी निकला है और बसु ने खुद कहा है कि हमारे खिलाफ तीन मिनिस्टरों ने लिख कर दिया है उसको कि यहां करप्शन भी हुआ है रिगिंग भी हुई है यहां लोगों को खराब भी किया गया है। हम आपको पूछते हैं कि यह क्यों हुआ है? वह खुद माने कि तीन मिनिस्टर उसको कह रहे हैं। हम लोग उसमें क्या करें? वह सारी चीज कहीं न कहीं सब के सामने निखर कर आयेगी कि कैसे आपस में कितना उनका गठजोड़ है। यह तो उस सूबे की बात कर रहे हैं जहां कि कहते हैं कि क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश की बात की थी वहां पर क्या नहीं है? अदालत ने फैसला किया हुआ है। किस सूबे में नहीं है आप मुझे बता दीजिए। मैं इसके सबूत दे सकता हूं कि जिस सूबे में हमारे उल्ट सरकार है आपोजीशन की सरकार है वहां किसी ने फेवरटिजम किया है। किसी ने वेपोटिजम किया है किसी ने करप्शन की है। उन सब की बातों को इकठ्ठा करके हम पर क्यो लादते हो? प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा है यहां मैं नाम देना नहीं चाहता, अभी डिसकशन हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आने दो रिपोर्ट उसमें जो भी होगा वह लोगों के सामने रखेंगे।

बड़े से बड़ा आदमी उसमें इन्वोल्व होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। यह बात उन्होंने बार-बार कही है, फिर भी यहां पर बार-बार इस तरह की बात उठाना, जिसका कि हमें अधिकार नही है और वह भी इसलिए उठाई जाती है ताकि इस इस्यू को कायम करके लोगों को यह बात कहते जायें क्योंकि हिटलर ने यह बात कही थी कि बार-बार एक झूठ को कहो, बार-बार उस झूठ को कहो ताकि वह झूठ सच में तब्दील हो जाय। सिर्फ यही सारी चीज है और कोई बात नहीं है।

उपसभापति महोदया, मैं यह कहता हूं कि जितने भी इस्यूज यहां उठाए गए है गवर्नमेंट की तरफ से, उनमें से एक बात यह भी है कि इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाहर की ताकत से गठजोड़ रखते हैं और वे कही किसी जगह पर कहीं किसी दूसरी जगह पर अपने मूंह दिखा रहे हैं। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहता हूं मैं साबित कर सकता हूं कि कुछ आदमी हैं जो इस बात में पड़े हुए हैं।

इसके अलावा में त्रिपुरा की बात करना चाहता हूं। यहां बहुत शोर हुआ कि त्रिपुरा में फौज क्यों गई? आप खुद, त्रिपुरा सरकार से पूछें कि उन्होंने इसकी मांग की थी कि नहीं कि यहां पर आकर कंट्रोल करें। कंट्रोल हुआ। लेकिन जब आप चुनाव हार गए तो यह कहना शुरू कर दिया कि फौज यहां क्यों बुलाई गई? फौज ने कोई कत्ल नहीं किया, इसमें फौज का कोई काम नहीं है बल्कि उन्हें जो लॉ एण्ड आर्डर के लिए हिदायत थी, जो दुश्मन हमला कर रहे हैं, जो तोड़-फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बंदोबस्त की हिदायत थी, वह उन्होंने किया बाकी जो है नार्मल एडमिनिस्ट्रेशन, वह उनके हाथ में था। अब जब चुनाव हार गए तो यहां यह बात शुरू हुई कि फौज को क्यों बुलाया? आप वेस्ट बंगाल में देखिए उन्होंने खुद माना है, तीन मिनिस्टर ने

खुद लिखकर दिया कि यह हालत हुई है, लोगों की मार-पीट हुई है, यह सारी चीज उन्होंने मानी है। तो आप समझ लीजिए, खुद करने वाले लोग ऐसी अंजामबाजी करते हैं कांग्रेस ने यह किया, वह किया। मैं तो समझता हूं कि प्राइम-मिनिस्टर को हमें इस बात की मुबारकबाद देनी चाहिए कि जो ऐसी ताकतें वहां डिस्ट्रक्शन कर रही थीं, जो लोगों को तोड़ रही थी, बाहर से हथियार आकर लोगों को मार रहे थे, न सिर्फ उनका बंदोबस्त किया बल्कि उसके नाम पर सरकार भी चलती चली गई है, जो अपने आपको मार्कसिस्ट कहते हैं। हम उसके खिलाफ नहीं हैं मगर जिसमें जितनी ताकत ज्यादा हो, वह आए और सरकार चलाए लेकिन यह नहीं कि सरकार अगर किसी की बन जाय तो यह कहना शुरू कर दे कि गड़बड़ी हुई है, यह हुआ है, फौज ने वह किया है फौज का नाम मत लीजिए मैं बराए खुदा आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि फौज इस बात के लिए नहीं है कि इस हाऊस में उसे कण्डेम किया जाय या उस बारे में कुछ चर्चा ऐसी की जाय। हमारी फौज सारे हिंदुस्तान की सेकुलर फौज है, उसमें हिन्दू, मुस्लिम सिख, इसाई सभी हैं और वे सब मिलकर हिन्दुस्तान की हिफाजत के लिए, हिन्दुस्तान की सरहदों को मजबूत रखने के लिए काम करती है। इसलिए उनका नाम यहां मत इस तरह लीजिए। आप हमारे खिलाफ अंजाम लगाते हैं, लगाइए, यहां पर सब कुछ खुला रूप है, यहां सब कुछ आप कह सकते हैं। लेकिन मेरी अर्ज है कि आप यहां पर फौज का नाम मत लीजिए। मुझे शक है कि कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे नासूर मौजूद हैं, जो घुसकर ऐसी बात को कह रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फौज का नाम लेकर ऐसी बात न करें।

उपसभापति महोदया, अब मैं पब्लिक सेक्टर की कुछ बात कहना चाहता हूं। यहां बहुत शोर इस पर मचाया गया। हम कहते हैं कि अगर इसमें इतनी खराबी है, उसको दूर करने की जरूरत है, दूर करें, इसमें शक नहीं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है, इसको मजबूत करना जरूरी है। इस पर प्रधानमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि और उनके अलफाज का इस्तेमाल करके कुछ दूसरी पार्टियों ने यह कहा है कि पब्लिक सेक्टर में यह सरकार यकीन नहीं करती। उन्होंने कहा है कि कमांडिंग हाइट, हम चाहते हैं कि इसमें लाएं ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई चीज हो, जिसमें पब्लिक सेक्टर हमारी इनडिजनेस इन सारी चीजों को देख सकती है उसमें एम्पलायमेंट करा सकती है, यह ठीक है कि अनएम्पलायड यूथ है, जो पढ़ा-लिखा है जो उसको जगह देने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ावा देने की जरूरत है।

महोदया, अब मैं चाहता हूं कि दो तीन तजवीज मैं अपनी दूं। यहां हमारे दोस्त, मिनिस्टर साहब, साठे साहब बैठे हुए हैं, इनसे अर्ज करना चाहता हूं जितनी आज हमारी बिजली है, कारखाने की ग्रोथ के लिए, इण्डस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए निहायत जरूरी है कि आप एक बात करें और वह यह कि जितने हमारे थर्मल-प्लांट हैं इसमें 10 फीसदी, 20 फीसदी और बढ़ाया जा सकता है, उसको रिपेयर करके, उसका रिकंडीशण्ड करके, उसको सारी चीज दुरूस्त करके जितना किया जा सकता है, करें। इसके लिए जो बाकी और बड़े कारखाने लगाने में पैसे की जरूरत पड़ेगी, वह नहीं पड़ेगी क्योंकि 1/5 आबादी जो आज 30-35 हजार मेगावाट क्षमता है तो इस 30-35 हजार मेगावाट में अगर आप 20 प्रतिशत बढ़ा सकेंगे तो आपकी करोड़ों रुपये की दौलत जो है, वह बचेगी। जो किसी और तरफ मोड़ा जा सकता है क्योंकि आज जरुरत इस बात की है। मैडम, हम जानते हैं कि आज जो भन्डार अधिक बन पाये हैं, वह हमारी सरकार के वक्त के हैं। आज भंडार इतने ज्यादा इसलिये बन पाये हैं क्यों कि आधा पैसा इस बात के लिये दिया जाता था कि हमें बिजली कैसे ज्यादा-से-ज्यादा पैदा करनी है। हमने 900 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा की। 1952 से लेकर 1980 तक उसे हमने दुगना कर दिया जिसका यह नतीजा है कि आज वहां से सबसे ज्यादा फूड ग्रेन सेंट्रल पूल में आया है। वहां 5 लाख ट्यूबवेल लगाए गए और उसकी वजह से इतना अनाज पैदा हुआ। ड्राउट हर कहीं था। जहां दूसरे सूबों में था वहीं पंजाब में भी था। लेकिन वहां के लोगों ने हिम्मत से काम करके अनाज की पैदावार को आगे बढ़ाया है। इससे हालात और ज्यादा अच्छे

[श्री दरबारा सिंह]

होंगे । इस एग्रीकल्चर सैक्टर को आगे बढ़ाना निहायत जरूरी है । आप उनको जितनी ज्यादा-से-ज्यादा सहूलियतें दे सकते हैं, दीजिए । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो लैंड लार्ड बने हुए हैं, उनको पीछे कर के लैंड रिफार्म को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि जो गरीब-हरिजन हैं जिनको हम टेनेंट कहते हैं, जब उनकी तरफ तवज्जो देते हैं तो वे उठकर आवाज देते है कि रिलीजन इन डेंजर। धर्म खतरे में है । इस बात को खत्म करने के लिए निहायत जरूरी है कि हम उनकी ओर तवज्जो दें । मैं जानता हूं कि यह आहिस्ता आहिस्ता होगा । लेकिन यह करने की जरूरत है । आज सेनाएं जो सूबों में पहुंच रही हैं और किसी-न-किसी नाम पर खराबी आपके सामने आ रही हैं, वह इसीलिए हैं कि वे लोग जो सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन पर बैठे है और गरीब लोगों को, हरिजन लोगों को मार-मारकर उनका कचूमर निकाल देते हैं । वे जो हमारी पुरानी कल्चर है उससे दूर रखना चाहते हैं । इसलिए यह एक निहायत जरूरी बात है

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । अंग्रेजी में यह कहते हैं कि "वी शुड गो बैक टू द विलेजेज ।" हमारे 80 फीसदी लोग देहात में रहने वाले हैं, उनको सारी चीजें देने की जरूरत है आप बीस-बीस या पचास पचास गांव हैं उनमें छोटी इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को ले जाएं जिसमें वे लोग काम करें ताकि गांवों की आबादी को जो शहर की तरफ माइग्रेशन हो रही है, कम किया जा सके और वे वहीं बैठकर अपना गुजारा कर सकें । उनकी ग्रोथ रेट बढ़े । उनकी खरीदने की शक्ति बढ़े, ताकि वे वहीं बैठकर अपनी जरूरियात की चीजों को प्राप्त कर सकें । बेअर नेसेसिटीज आफ लाइफ जो है, वह उन्हें तभी मिल पायेगी, अगर वे अपने घर पर रहते हुए काम कर के, अपना गजारा करके जिन्दगी की जो जरूरियात हैं, उनको पूरा कर पायें । अगर आप इसके लिये कोई तजवीज कर सकें, तो अच्छा है । आज हर सूबे में पिछले 40 सालों में बहुत कुछ हुआ है । जो एक खाली हिन्दुस्तान मिला था, उसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी जी ने लगातार मेहनत कर के इस देश को बनाया है । इन्टरनेशनल लेवल पर आज भारत एक ताकत बनकर उभर आया है । आज डिक्लरेशन चाहे दिल्ली में हुआ हो या कहीं और हुआ हो, आज हिन्दुस्तान की पूछ है । हमारे इस नौजवान लीडर ने आज हिन्दुस्तान की तरक्की करने के लिये हिन्दुस्तान को विश्व के नक्शे पर ऊंचा उठाया है, जहां से कि वह आगे बढ़कर बड़ी-से-बड़ी ताकत बन सकता है । दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम हो सकता है । दुनिया से न्यूक्लिअर वीपंस को हटाने के लिये पूरा जोर लगाया है । मैं कहना चाहता हूं कि गोर्बाचौफ ने निहायत हिम्मत से यह काम किया है । हम उनकी जितनी सराहना करें, कम है, क्योंकि उन्होंने बात ऐसे लोगों से की, जिनको वह इंपीरियलिस्ट मानते हैं, कपेटिलिस्ट मानते हैं उनके घर पर जाकर यह फैसला किया कि हम कम-से-कम 3 परसेंट न्यूक्लिअर वीपंस को खत्म करें । उन्होंने कह दिया है कि अफगानिस्तान से हम फौजें ले जायेंगे । अब उनको चिन्ता हो रही है कि फौजें ले जायेंगे तो क्यों ले जायेंगे । पाकिस्तान हमारी सरहदों पर भारी तादाद में भीड़ इकट्ठी कर रहा है और दूसरे मुल्कों से हथियार इकट्ठा कर रहा है । उधर सिंकाचीन में हमारी सरहदों पर भारी सख्या में फौजें जमा हो रही हैं । इसलिये हमें अपनी सीमाओं की, अपनी सरहदों की सुरक्षा करनी है । अगर दुनिया में शान्ति और अमन करना है तो हिन्दुस्तान को इसके लिये ताकत हासिल करनी होगी और दुनिया के मुल्कों को बताना होगा कि वे अरबों खरबों रुपये के जो हथियार जमा कर रहे हैं उससे हिन्दुस्तान पर भारी दबाव पड़ रहा है । हमें अफसोस इस बात का है कि फिर भी लोग आज यह कहते हैं कि बाहर की पालिसी तो अच्छी है, लेकिन अन्दर की नहीं । अगर बाहर के लोग आपको खाने के लिये आ जायें तो आप क्या करेंगे ? 16 हजार फीट की बुलन्दी पर हमें मारने के लिये

पाकिस्तान ने कौन से हथियार नहीं लिये हैं? हमारी सरहदों पर वह क्या नहीं कर रहा है ? नए नए प्रोड्क्ट्स और न्यूक्लियर मिसाइल हासिल करके वह किस पर इस्तेमाल कर रहा है ? दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क तोड़ फोड़ करने वालों को आगे बढ़ा रहे हैं यह भी हमको देखने की जरूरत है।

एक बात और कहना चाहता हूं। दुनिया के देशों को आज हमें टेरोरिज्म और सेपरेटिज्म को खत्म करने के लिये मदद करनी होगी और किस तरह से रास्ता साफ किया जाये इसको देखने की जरूरत है। अगर यह नही किया तो हम हिन्दुस्तान को तबाह कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान रहे, हम अगर चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में रहने वाला सुरक्षित रहे, हिन्दुस्तान रहे तो अगर हिन्दुस्तान नहीं रहेगा तो कौन हिन्दुस्तानी कहलाएगा, यहां कौन हिन्दुस्तानी रहेगा ? चाहे हिन्दू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मुसलमान हो, सभी हिन्दुस्तानी तब है, जब हिन्दुस्तान रहेगा। अगर हमारे उपर हमला होता है तो वह हिन्दुस्तान पर हमला है, किसी कौम पर, किसी शख्सियत पर हमला नहीं होता है। इसलिये लोगों को मजबूत करने की आज जरूरत है। उसको मजबूत करने के लिये पैसा लग रहा है। हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे तो उस के लिये हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है। हम भी जानते है कि वह पैसा लोगों की जगह नेसेसिटीज पर खर्च हो, लेकिन हमें मजबूरी में अपनी सुरक्षा के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है ताकि हिन्दुस्तान मजबूत रहे, हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी सटेलाइट निकाला है, न्यूक्लियर ताकत जितनी हमारे पास होगी, उसका हम अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। हिन्दुस्तान चाहता है कि उसका इस्तेमाल शांति के लिए हो हम डेवलपमेंट चाहते हैं डिस्आर्मामेंट चाहते हैं उसके लिए हम आगे बढ़े तो तभी शांति हो सकती है।

और ज्यादा न कहते हुए मैं आपसे यही कहता हूं, अपील करता हूं कि आप आइए, इकट्ठा होकर सोचिए कि हमारी 80 फीसदी आबादी जो देहातों मे रहती है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। वी शुड गो टू दि रूरल एरियाज। हम अपनी इकानामी को उस पर खर्च करें, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हम सब मिलकर इस बात के लिए प्रयत्न करें। इसलिए जो रेजूलूशन आपके सामने है, जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और सब से यही कहता हूं कि प्रेसिडेंट आफ इंडिया ने उसमें एक एक लफ्ज जो कहा है, उस को हम देखें, उस पर विचार करें। कौन कौन से हमारे डेवलपमेंट के एरियाज है, कहां पर हमें काम पहले करना है, कहां पर मुल्क को ले जाना है, इसके लिए लोग आपस में मिल बैठकर विचार करें। सारी की सारी बातें खोलकर उसमें रख दी गई है, उनमें से हमने बहुत कुछ हासिल किया है, और क्या करना है उस पर हम ध्यान दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमें आज जरूरत इस बात की है कि हमने लगातार जो सौ साल तक लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने सब सूबों मे मुल्क की आजादी के लिए काम किया, कोई फासी पर लटके, कोई जेलों में सड़कर मरे, घर के घर बरबाद हुए, तब जाकर हमें आजादी मिली। इसके लिए जो फ्रीडम फाइटर है, उनकी तस्वीर, हर किसी की तस्वीर हमारे अपने सूबों के अंदर बनानी चाहिए कि हिन्दुस्तान के लिए इन्होंने कुरबानी दी ताकि हमारे बच्चों, छोटे बच्चो को हम दिखा सकें कि किस साल की लड़ाई किस पार्टी लीडर के आधार पर 1947 से पहले लड़ा, आजादी के लिए इन्होंने काम किया तभी यह मुल्क आजाद हुआ। इसका नक्शा हम उनको दिखाएं ताकि आने वाली जनरेशन को पता लगे कि हमारे बुजर्ग ने इस महल की बुनियाद कैसे बनायी है अपना खून पसीना और हड्डी दे कर इस को बनाया है। आप को बुनियाद दिखाई नहीं देती। आज के लोगों को बुनियाद दिखाई नहीं देती। उस पर खड़ा हुआ महल ही दिखाई देता है। उस को इरेज करने वालों से इस को बचाइये। और बच्चे जो उस समय उस को बनाने में हिस्सा नहीं ले सकते थे उन को कम से कम वह ज्ञान दें कि आप के बाप दादों ने यह काम किया है।

[श्री दरबारा सिंह]

इस से उन में पैट्रियाटिज्म आयेगा और आगे डेमोक्रेसी मे काम करने के लिये, दुनिया में पी। कायम करने के लिये, उस के डवलपमेंट के लिये, और देश को आगे बढ़ाने के लिये, जो काम होगा उस में उन की कोशिश रहेगी और यह बात हमेशा उन के दिमाग में रहेगी और ऐसा होने से हिन्दुस्तान एक रहेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं।

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu): Madam, I thank you for the opportunity given to me to speak on the President's Address. I praise the President but despise the President's Address. I oppose the Motion moved by the hon. Member, Shri Kulkarni.

The President's Address does not mention about price rise. Today there is all round increase in the prices. The Government goes on taxing the people all through the year. Price of rice is beyond the reach of the common man. The price of sugar is bitterly high. The edible oil has become inedible. The hike in yarn prices has thrown lakhs of labourers out of job. The common man has lost his communication link because of the hike in postal tariff. A painful mockery of democracy has come in the form of increased money-order commission. The trains are running slow, but the fare is running super fast. As we are obtaining more and more oil from natural resources, we go on increasing the price of petrol. This is a telling example. You can never control the price rise. The prices of various articles, such as steel and coal, have also gone up. Poor and middle class people are facing a lot of difficulty as a result thereof. So I charge that this Government is totally anti-people.

During the regime of the darling of the poor, Dr. MGR, in 1983 when the production of rice was only 28 lakh tonnes as against the requirement of 65 lakh tonnes, the price of rice did not go up. But now within one month of President's rule in Tamil Nadu, the price of rice has gone up by rupee one per kilogram. As an able administrator Dr. MGR could contain the price rise for over a decade—i.e. from 1977 to 1987.

Madam, in the President's Address, no mention has been made of the problems faced by farmers. In India 70-80 per cent of the population is that of farmers and labourers. But their problems still remain to be solved. Bank loans and subsidy do not reach the farmers. Government should fix the maximum credit limit of the farmer on the basis of the land owned by him. Farmers and labourers are still facing great financial hardship. If farmers are provided water and electricity, their condition would improve to a great extent. You should have an open mind and take inspiration from the policies of our beloved MGR. He could give free electricity connections for more than 10 lakh small and marginal farmers. The Centre should take the initiative to implement the scheme all over India.

There is unemployment problem all over the country. The Government has expressed not only its inability but also lack of political will to tackle the problem of industrial sickness. The Government has no policy to remove sickness in industries. As a result, year after year, more and more industries are becoming sick. The number of sick industries has reached a figure of 1,20,000. Millions of people have been thrown out of employment.

1. P. M.

In the industrial sector, the textile industry, the sugar industry, the paper industry, the fertilizer industry and the pharmaceutical units—all are in crisis.

The number of educated unemployed in the Employment Exchange registers, which was 3 lakhs in 1951, has risen to 301 lakhs in 1986 and must have crossed 400 lakhs in 1988. Each year the figure of the unemployed is increasing.

After spending Rs. 2,80,000 crores up to 1986 and 1987 on the Five-Year Plans, the greatest achievement of the Government is that today 30 crore

people are below the poverty line. The per-capita income has gone down. That means, the poverty is terribly increasing day by day.

Today there are separatist movements all over the country. There is a demand for separate Khalistan. There is a demand for separate Gorkhaland. There is a demand for separate Jharkhand. Apart from that, we find insurgency in the form of TNV in Tripura, G.L.F.A. in Assam, N.S.C.N. in Manipur.

The peasants in the field, the workers in the factories, the employees in the offices—all are revolting against the Government. The lawyers are on strike. The doctors are raising their voice against the Government. This is the sad state of affairs in India. This is the achievement on the 40th year of the independence.

Because of the erratic pattern of rainfall, there is drought all over the country. Today more than 1,40,000 villages do not have drinking water in India. But millions of TMC of water is flowing waste into the sea.

Late Dr. MGR's repeated request to the Centre was to take steps to divert the surplus waters of the west-flowing rivers of Kerala towards Tamil Nadu. I feel, the Centre has no time to think about that.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Janaki's request, not MGR's.

SHRI M. VINCENT: I am coming to the point. Please wait for a moment.

There are three schemes for which late Dr. MGR had Central clearance. *(Interruptions)*

MGR was the noblest embodiment of unity.

Late MGR had asked for the Central clearance. These are with foreign financial assistance. They are:

(1) Research and Development Centre for Pumps and Motors at Coimbatore with aid from the Republic of Germany.

(2) Auto parts development centre at Madras with the help of the Italian Government.

(3) Modern Toolroom Training Centre at Coimbatore with the help of Denmark.

The State's share of these three schemes, is being invested in instalments. It is for the Centre to allot their part of the expenditure. I request the Government to come forward with the clearance as early as possible, since 90 per cent of the cost of these projects is borne by the foreign governments.

I would like to add that in Tamil Nadu the late, lamented leader, Dr. MGR's Nutritious Noon Meal Scheme is a landmark in feeding the poverty-stricken school children. Every day 88 lakh school children are being fed. I request that Tamil Nadu may be financially helped to improve further the Scheme with the Integrated Health Programme. Such a scheme may be introduced all over India in commemoration of Dr. MGR as a mark of respect.

The misadventure of this Government in Sri Lanka is a classic example of the inefficiency of this Government. The Indo-Sri Lanka Agreement is with the consent of our beloved late Dr. MGR, I agree. But the assent given by MGR was not totally unconditional. In the Agreement there was no provision to act against the Tamils. Man-hunting and man-slaughter are going on unabated. Dr. MGR had agreed because this Agreement was originally framed for the welfare and peace of Tamilians, but you misused it. One month back the gents were forcibly evacuated from their houses while the virgins were at home at Mattakalappu. It is an unpardonable sin you have committed against the sanctity of our Tamil women. I condemn your attitude. So long as our charismatic leader, Dr. MGR was alive, you could not arrest even a single Sri Lankan Tamilian in Tamil Nadu. It proves MGR's consent

[Shri M. Vincent]

was conditional and limited. India's peacekeeping force is for peace, not to put the agreement into pieces. Giving a fitting reply to Jayewardene in 1982, our Tamil pride, Dr. MGR said: "If the Tamilians are not protected in Tamil Nadu, where else they would be protected?" This was asked by our late MGR in 1982. Now in 1988 after the demise of MGR you are arresting Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu. Stop your action. I demand immediate release of the arrested Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu. Sri Lankan Tamils are staying in Tamil Nadu because it is their birthright. Delhi cannot interfere. Delhi has no business to do that. More than a thousand Indian soldiers had been killed in Sri Lanka. Who is responsible for this? This Government is responsible for this. Why are you killing our Tamilians and killing our Indian soldiers? Our Prime Minister is born for Accords, but all his efforts are in failure. That is his record.

Our originally democratic Constitution has become highly undemocratic and highly unitary. The Central Government has increased their power from time to time in a most arbitrary manner. The power under Article 356 of the Constitution, viz. imposition of President's rule in the State has been used more than 80 times in 40 years. It was unfortunate that our President who hails from Tamil Nadu had to deliver his first Address to Parliament after dissolving the Government of his own State of Tamil Nadu. I can imagine the degree of torment that the noble heart would have undergone. Mrs. Janaki MGR's Ministry was dissolved. The reason stated was Constitutional breakdown. The question is who broke the Constitution? Who created the turmoil in the Assembly? It is the Congress(I). In the morning at 10.30 Shivaji faction Congress MLAs, Ilango and others were beaten brutally. By whom? By Congress MLA** their Dhoties were removed. By whom? By Congress MLA**. Who walked away with mikes? It was the Congress MLAs. Who attempted to sit on the lap of the Speaker? It was your Congress MLAs, who had thrown chairs? It was your Congress MLAs.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Names will not go on record. (*Interruptions*) Don't mention the names of those who are not here.

SHRI M. VINCENT: It is the Congress and Congress alone that created the turmoil in the Assembly. What das the necessity of the physical presence of Pondicherry Chief Minister in the Assembly? Why was the Central Minister** sitting on the Speaker's gallery on that day? That means you had preplanned the conspiracy. Your preplanned conspiracy was thwarted by our iron man P. H. Pandiyan. My open allegation is you have indirectly attempted to snatch power in Tamil Nadu. Let me remind you that will not happen in the history of Tamil Nadu. As you all know, Punjab State Assembly was dissolved because of terrorism. But Tamil Nadu State Assembly was dissolved because of Congress-I terrorism. Don't think that you have dissolved Mrs. Janaki Ramachandran's Ministry. You have dissolved your own Congress party in Tamil Nadu. Your party has been shattered into pieces. Now you have four factions, Moopanar faction, Sivaji faction, Subramanian faction and Bhuvarahan faction. You will not come to power in Tamil Nadu. you have committed a sin against the holy mother—Mrs Janaki Ramachanran. I want to tell you what you sow, you will reap. Thank you.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Madam the Deputy Chairman, I congratulate the President of India for his message to both Houses of Parliament. Till recently he was our Chairman. I call this message as people-oriented message.

**Not recorded.

**Not recorded.

I request my hon. friends in the Opposition that while they offer their comments they must develop a proper sense of appreciation of the questions. It is true that we are faced with a situation of removal of poverty in this country, but consider the speed with which the population of this country is growing and if with that speed the production does not grow then the problem really lies in the removal of poverty. Even the production which we have achieved will be nullified by more population production. For the removal of the poverty our learned Prime Minister and his Government are approaching the problem. Technological revolution in this country for which I must congratulate our Prime Minister and the Government. Every department of the Government is having its own R&D wing. The other day when a surface-to-surface missile was fired all the Opposition parties congratulated the R&D wing of the Defence Ministry. They have achieved the results meticulously. For the first time our great scientists have developed a surfact-to-surface missile without any technical know how from abroad. That is the approach and that is how our Government is working. It is very easy to borrow technology or steel the material or know-how as Pakistan has done. But when a Government has reached the point of self-sufficiency with its Scientists, it can produce results and can fire missiles to a distance of 250 kilometers. I feel that is the real thrust of the question. It is not only in the realm of defence or defensive weapons but in all fields of life. That is why I call our President's message to both Houses of Parliament as a highly people—oriented message.

The hon. President has said that the primary goal of amelioration is eradication of poverty. It is the most important goal which can be achieved only with the help of technological revolution in this country. I am not one of those people who are under a wrong impression that we can develop all technologies ourselves in this country. We will have to purchase it. We will have to bring it from outside but it is a very costly phenomenon. If you want to see the real development in this country, then we will have to exert more. In respect of the present Five Year Plan, we are left with only half of the period. In the remaining two Five Year Plans, that is 8th and 9th, within 13½ years, you have to take this country forward with such a speed that tears are wiped out from every eye of every citizen of this country. Now how to do that is the basic question and I am sorry to say that our friends in the Opposition have not responded well to this desire of our leadership to usher in technological revolution in this country so that within 13½ years, we can progress so much that our poverty is removed and we are in a position to stand in the category of developed nations. There is nothing wrong with this ambition of our leadership. Now it is our resolve that the nation can be strong and the nation can progress if all sections of people get equal opportunities to come forward and there are no disparities left among the people. There should be full employment for everyone. I completely assert this. The message is there. The way to reach that goal is also there which should have been appreciated. The President is quite right when he says, we are unflinching in our determination to root out communalism, fundamentalism and fissiparous tendencies. These are our real enemies. We have to crush them with determination if not with a heavy hand. My learned friend was very much eager to point out that but the whole nation realises it. The question is what is the solution? How do you want to tackle the problem?

Now the President, in his Address, from paragraph number 29 to 35, has referred to the goals of science and technology which deserves real attention of this nation. In this connection, the President mentioned the establishment of five tech-

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

nology missions. Some Members of the Opposition said, if you believe in taxing the people, then we do not want these technology missions. May I ask them then how rapid progress is possible? How can the nation achieve the growth rate which they want the Government to achieve? If he wants to incur expenditure, then you say, we do not need that sort of technology mission. This is not a very responsible statement of the Members of the Opposition. This is the only way by which rural poverty can be ameliorated, rural growth can take place and when all our schemes under 20-Point Programme and various other national development programmes can be implemented. It is in order to remove poverty from villages, to remove unemployment from villages that we have established these five technology missions for which I congratulate the hon. Prime Minister and the Government because without it, you cannot remove poverty from this country. The success of these missions will bring the benefits of the science and technology to the ordinary man. It is indeed a sad reflection on our ability that in spite of our vast scientific and technological resources, we are still unable to provide drinking water, functional literacy and the basic necessities such as edible oils etc. etc. to our villagers. But, the key to all these problems is only a technological revolution in this country which does not find any appropriate appreciation from the hon. Members of the Opposition. I propose that there should be a closer interaction between Parliament and the technological missions. This is my first suggestion for the hon. Minister for Parliamentary Affairs to note down. Parliament should get full information of the working of the technological missions and should lend support to them in the implementation of the various schemes to be launched by them. Unless and until we get in close touch with those missions in their day-to-day working, we cannot have the supervisory jurisdiction over them which is the need of the hour. The President has also mentioned about the progress we have made in the areas of energy, electronics, nuclear power and remote sensing which are very important areas for the modernisation of the country.

Now, the hon. Leader of the C.P.I. (M) when he debated, expressed his misapprehensions about modernisation. What he means by modernisation or computerisation is, perhaps, mechanisation. (*Interruptions*) Modernisation and computerisation do not necessarily mean creation of unemployment, which was the basis of his misapprehension. Let me say here that I am against anything and everything which makes people unemployed or which creates unemployment. But when there is the need to provide people with necessities of life, of improving the living standards of the common man, if technology can help it, we must make use of it. We will make good use of it. In other words, we need to increase production through improved techniques and technology without creating unemployment, to make necessities available to the common man. This is what I call modernisation and not what the learned Leader of the Opposition said. You cannot stall everything in the name of unemployment. I am against unemployment. But you cannot stall everything by that bare argument. Modernisation is not mechanisation. We have to harness our mind forward. Unlike the thinly populated western countries, we cannot afford to make human beings redundant. But I am for all modernisation which aims at optimisation of the scarce resources and higher production and less wastage. I think this will clear the misapprehension of the hon. Member.

As far as industry is concerned, the emphasis is on upgradation of the skills of workers and better amenities for them. More and more jobs should be created for more and more workers. At the same time we need to modernise our decadent industry and means of production to create the highest standard of living for the common man. Computerisation should be a part of the modernisation process. We should use computers to increase efficiency and productivity and not for taking away such jobs which may be very well performed by our labour force. We should use computers in such a manner as would open more areas to employment. (*Time bell rings*)

My last point—since you have rung the bell—is there is a lot of misnomer about induction of technological revolution in the field of agriculture. People are making speeches that the thrust of technological revolution has not been properly inducted into the realm of agriculture. I think there is a complete lack of information. In the last two or three months I have been in touch with the Pusa Institute here in Delhi and other agricultural research institutions in Patna, Pantnagar, Faizabad, etc. and I can tell you that our scientists have made such big researches in the field of agriculture that even America and USSR are looking up to our researches. In the field of biotechnology, in the field of tissue culture, in the field of genetic engineering, etc. our scientists have made such a lot of progress in their research. Take the very concept of a tree, the root, the trunk, the branches, the leaves, the flowers and the fruits. You can have the fruit right from the beginning of the tree itself. This is the technological revolution that our scientists have brought in India and the world is looking to our research. But here people express such ignorance. Somebody was talking of lower varieties both in rabi and kharif crops. I have seen in my own fields, tremendous results have come. When I was coming back from my districts, till Allahabad our fields were full of mustard product. Our Products are safe and I hope there will be no hailstorm—I pray that there will not be any. And then we shall remove that imbalance in mustard oil, vegetable oil, which we have to import from other countries. But how is it possible? (*time bell rings*) Madam, I wanted to say so many things on agriculture. About technological revolution which is now being implemented in the realm of agriculture. I wanted to speak—but for paucity of time I won't be able to do it. But I may tell you that our scientists in our research laboratories, in our agricultural universities, have brought about far better results than other people are doing anywhere else in the world, I must compliment our scientists, our great scientists. That is why I have raised my voice for granting parity in their pay-scales. If this technological revolution really succeeds in India, I am sure within these 11-1/2 years, by the commencement of the next century, really the poverty of this country will be removed, the tears from the eyes of the poor people will be wiped out and what Gandhiji contemplated would become successful. But it requires a proper appreciation of and a proper approach to the President's Address, to the efforts of the Government, to the thrust that the leadership of the Congress Party has created. With a prejudiced mind we cannot judge it. We must have a proper perspective. (*Time bell rings*)

Madam, since you are not giving me time, I cannot dwell on the other very important points. I have many arguments to advance but I conclude with these words.

THE DEPUTY CHAIRMAN Now the House stands adjourned for lunch and will meet at 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now, Mr. J. S. Aurora.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, with due deference to the President for whom I have the greatest respect, I must say that the Address presented by him has been singularly uninspiring. It is full of good intentions and platitudes. But the record of performance as shown in the Address is distressingly diappointing. Our vision as contained in paragraph 3 of the Address sounds impressive. But to date actions believe the pious hopes. The Government is neither sincere nor capable of fulfilling these hopes. During the last year the Government has done little to crow over but much to answer for. The nation today is more divided than ever before. Fissiparous tendencies have increased. The situation in Punjab has gone

[Shri Jagjit Singh Aurora]

from bad to worse. The Presidnet's rule has been a disaster. Bereft of political savy the Government has single-mindedly continued to use oppressive measures and terror to control the law and order situation. It has only achieved greater bitterness and alienation. Killings have increased and the people of Punjab have lost the confidence in the Government's ability to rule justly or effectively or fulfil the promises made. The hon. Members from the treasury benches have always tried to find scapegoats for the Government's mishandling and incompetence, for their inability to handle vital situations effectively. This convinces nobody.

The Ram Janam Bhoomi and Masjid Babri controversy remains unresolved. It is a festering wound which can burst at any time. The GNLF holds the hilly areas of West Bengal to ransom, and most of the small States in the east are distrurbed and unsettled to a varying degree. There appears to be little realisation that the internal weakness is a far greater threat to the security of the country than any threat from outside; *viz*, rearming of Pakistan by the USA or the entry of foreign powers' navies into the Indian Ocean. Internal strength and solidarity is the greatest safeguard against any external threat. Sophisticated, modern weapons, though important, cannot ensure security for a house divided. The National Integration Council has remained dormant and ineffective, as the Government has not taken much trouble to revive it.

In spite of several schemes for eradicating poverty and controlling the burgeoning population, improving efficiency in agriculture and industry, the results achieved are not commonsurate with the resources employed. Nearly 40 per cent of the people continue to remain below the poverty line. Because of the unbridled increase in population, the actual prices are on the increase.

Policies for modernisation of industry have been inconsistent and slipshod. Public sector undertakings are a milestone around the country's neck, instead of having reached the commanding heights of the industry as claimed. We are a poor country. Ours is a high cost economy, which makes as uncompetitive in the international market. In practical terms, very little has been done to improve this situation.

We talk about moral and spiritual values, whereas corruption has reached the commanding heights in all Government agencies. No wonder, we are unable to control the mafias in coal-belts and smuggling across our borders, both by land and sea. The unholy nexus between criminals and politicians has enabled several criminals to enter our legislatures, thereby lowering the prestige and performance of the elected bodies. As regards social justice, the lack of it has been fully exposed by the Government's refusal to punish the guilty of the heinous crimes during the November 1984 carnage in Delhi and elsewhere in India. More recently, killing in and around Meerut give us another example whilst hundreds of innocent people are rotting in jails without trial. This is a shameful blot on the fair name of our country.

It makes me laugh when the Government claims to have built strong institutions to gurantee, the democratic rights of our citizens. To mention just a few. The Chief Ministers of the Congress-ruled States are not elected by the legislators as it should be, but are imposed by the Prime Minister or the President of the Congress Party from the Centre. Hence, there are frequent changes to satisfy pressure groups and the inability of the Chief Miniisters to control the legislators. This effects his administrative efficiency directly and inevitably.

The next is the office of the Governor which has become a dumping ground for the failed, ineffective and inefficient Congress leadrs. Worst still, it is being misused to create difficulties for the non-Congress ruled States. To top it all, what happened in the Rajya Sabha a few days ago when the Vice-President himself was placed in an unenviable position shows

little regard or respect for the established institutions. To my mind, even the institution of the Cabinet has been made ineffective during the last three years. With frequent changes in people and portfolios, decided arbitrarily, how can a balanced and well-integrated team be built up? No wonder it has resulted in the lack of coherent and rational policy-making which in turn, adversely affects the economic progress and security of the country.

This all-embracing Address is quiet on one subject of great importance, *i.e.* how does the Government propose to streamline the Administration and make it more efficient, result-oriented, cost effective and less corrupt? Without improvement in these fields, any number of planning cells task forces and commissions are not going to achieve worth-while results.

Finally, Sir, a morally and politically Government which is past redemption, cannot lead this country towards economic prosperity and national integration and well being

Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पूर्व संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है वह वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उनके संबंध में हैं । लेकिन जैसा कि इस तरफ के अनेक वक्ताओं ने कहा है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बिल्कुल नीरस था । उस में इस देश की जनता से न कुछ वायदे किए गए हैं, न आश्वासन दिया गया है और न उन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिनके लिए पहले जो लोक सभा के 1984 में चुनाव हुए और उसके बाद 1985 में जब वर्तमान लोक सभा गठित हुई और जो संयुक्त अधिवेशन हुआ उसमें जो वायदे किए गए थे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चुनाव सुधार से शुरू करूंगा । 17 जनवरी, 1985 को राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण दिया था, उसमें इस बात का वायदा किया गया था कि व्यापक रूप से चुनाव सुधार किए जाएंगे । उसके बाद 1986 में इस वादे को भूल जाने का काम किया । 1987 में थोड़ी चर्चा की गयी । इस संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण हुआ उसमें चुनाव सुधार के सिलसिले में कोई चर्चा नहीं की गयी । इस देश में जो चुनाव प्रणाली है उसके संबंध में सभी पक्षों की राय है कि चुनाव कानून मे व्यापक संशोधन होना चाहिए । इसलिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने इस देश के प्रबुद्ध लोगों से और जितने भी राजनीतिक दल हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रादेशिक स्तर के हैं या क्षेत्रीय स्तर के हैं उनसे बराबर इस सिलसिले में सुझाव मांगे । काफी राजनीतिक दलों ने सुझाव दिये भी लेकिन आज तक इस सिलसिले में सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी । इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती कि जो वर्तमान चुनाव व्यवस्था है, जो चुनाव प्रणाली है उसमें कोई परिवर्तन हो । क्योंकि आज चुनाव पर कालाधन हावी है, चुनाव पर बल हावी है और जिन लोगों के पास कालाधन है वे राजनीतिज्ञों को खरीदते रहते हैं । वे राजनीतिक दलो को खरीद रहें हैं । इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए । लेकिन इस बात की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है । यह इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार का इरादा चुनाव कानून में संशोधन करने का तनिक नहीं है । वर्तमान अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सरकारिया आयोग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आ गयी है । यह रिपोर्ट केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों के सिलसिले में है और इस पर राज्यों की राय लेने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी । सन 1983 ने केन्द्र और राज्यों के संबंध में सरकारिया आयोग की नियुक्ति हुई थी और करीब करीब चार साल तक सरकारिया आयोग ने मेहनत करके लोगों के बयान ले करके लोगों की राय लेकर के सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सरकारिया आयोग के केवल एक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह है राज्य-

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

पालों की नियुक्ति के संबंध में । रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है वह सरकार के पास विचाराधीन है । राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है कि सरकार इस सिलसिले में राज्यों की राय लेगी । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी, लोखों लाख रुपये इस पर खर्च हुए होंग लेकिन उसका उल्लंघन किया गया । उसको दरकिनार करके राज्यपालों की नियुक्ति की गयी । राज्यपालों के पद वाद विवाद के बन चुके थे तो सन् 1959 में पहली बार जब केरल में उस वक्त केरल को त्रावनकोर कोचीन कहा जाता था शायद विधिवत निर्वाचित सरकार थी उसके मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया गया और तब से राज्यपाल के पद पर बराबर यह आरोप लगाया जाता रहा कि राज्यपाल केन्द्र के इशारे पर काम करता है । केन्द्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करता है । इन सारी चीजों के बारे में सरकारिया आयोग ने अपनी संस्तुति दी । यह भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर ऐसा आदमी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय रूप से राजनीति में हो । दूसरी संस्तुति यह कि अगर किसी प्रदेश में विरोधी पार्टी की सरकार है तो वहां पर ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए जो किसी दूसरी पार्टी मे सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता रहा हो । जवाहर लाल नेहरू ने कंस्टीट्यूंट असेम्बली में जब राज्यपाल के पद पर विचार विमर्श हो रहा था उस वक्त यह कहा था :

The Governor must be acceptable to the Government of the Province.

इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी थी उसने इस सिलसिले में अपनी राय दी । लेकिन अभी हाल ही में तीन या चार राज्यपालों की नियुक्ति की गयी । एक राज्यपाल तो महिला है जो इसी केन्द्र ने मंत्रिपरिषद की सदस्या थीं । दूसरे एक ऐसे राज्यपाल हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में थे और सरकारिया आयोग ने यह भी कहा केन्द्र और राज्यों के संबंध अच्छी तरह से चलते रहें उनके संबंधों में सुधार हो, रिश्ते अच्छे हों इसलिए जो प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए । लेकिन हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा कि मुझ से पूछा नहीं गया मेरी राय ली नहीं गयी ! कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने भी यही कहा कि मुझ से पूछा नहीं गया मुझ से राय नही ली गयी । सरकारिया आयोग ने स्पष्ट अपनी संस्तुति दे रखी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको क्यों नही लागू किया जा रहा है । उसकी जो संस्तुतियां है उनको तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक केन्द्रीय सरकार अपने निर्णय नहीं ले लेती । उस आयोग ने स्वयं काम किया और इतनी मेहनत के बाद जब आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी तो उनका उल्लंघन करने का मतलब यह हुआ कि केन्द्र सरकार की मंशा यह नहीं है कि केन्द्र और राज्यों के संबंध अच्छे हों । केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि वह सत्ता में बैठी हुई है इसलिए विपक्ष के मख्य मंत्री यदि उनक सलाह से या उनकी राय के मुताबिक काम नहीं करते है तो ऐसी सरकारों को काम नहीं करने देंगे और राज्यपालों के जरिए इस प्रकार की सरकारों में परिवर्तन लाने और उनको गिराने का काम किया गया है ।

श्रीमन्, त्रिपुरा में चुनाव हो रहे थे । चुनाव के ठीक तीन दिन पहले त्रिपुरा को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहां पर तीन दिन के लिए भी इंतजार नहीं किया गया । वहां के तत्कालीन मुख्य मंत्री का कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, बिना मुझसे पूछे ही सारे राज्य को अशांत घोषित कर दिया गया है । वहां पर मिलिटरी और पैरा मिलिटरी फोर्सेज भेज दी गई । इसका मतलब यह है कि जितनी भी लोकतांत्रिक परंपराए हैं, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं सरकार उनको मानना नहीं चाहती है वरन् उनको गिराना चाहती है ।

मान्यवर, विधानमंडलो की बात लीजिए । अभी जनरल साहब जिक्र कर रहे थे कि जितने भी मुख्य मंत्री हैं, कम से कम सत्ता पार्टी के मुख्य मंत्री जो हैं, उनके नामांकन के सिलसिले में भी कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होता है ।

अभी राजस्थान के मुख्य मंत्री का बदलाव हुआ । सत्ताधारी पार्टी का मुख्य मंत्री हो या दूसरा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर विधान सभा में भेजे जाते हैं । जनता उनको अपना वोट देती है । हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए है कि जनता के प्रतिनिधि विधान सभा में जिस पार्टी का बहुमत हो, उसके नेता को मुख्य मंत्री बनाती है । लेकिन वहां जनता के प्रतिनिधियों की राय नहीं ली गई । राजस्थान विधान मंडल की बैठक नहीं बुलाई गई । मध्य प्रदेश के विधान मंडल की बैठक नहीं बुलाई गई । कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें तो इस बात की जानकारी तक नहीं थी । अगर किसी विधान सभा में डेढ़ सौ सदस्य थे तो वहां 40 भी सदस्य नहीं पहुंचे । इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो विधान की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके प्रति सरकार के मन में कोई आदर नहीं है ।

श्रीमन्, न्यायपालिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 9 जजों के पद दो साल से खाली हैं । लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं अपनी याचिका लेकर और अपने मुकदमे या अपील पर फैसले की प्रतीक्षा करते हैं । उनका ही फैसला करने में काफी विलंब होता है । तो इन 9 जजों की नियुक्ति कौन करेगा ? यह तो जनता नहीं करेगी । वह तो राज्य सभा या लोक सभा नहीं करेगी । इनकी नियुक्ति तो सरकार को ही करनी होगी । यह काम तो प्रधान मंत्री का, गृह मंत्री का है और केन्द्रीय सरकार में उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है । लेकिन पौने दो साल से सर्वोच्च न्यायालय में ये पद खाली रहे । इसका मतलब यह है कि सरकार की इच्छा है कि ऐसे जजों की नियुक्ति की जाए जो प्रधान मंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से कमिटेड हों, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति कमिटेड हों वरना इतने बड़े देश में 9 वकील न मिलेंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जा सकें । इसी प्रकार से चार उच्च न्यायालयों में, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थानापन्न न्यायाधीश काम कर रहे हैं । इसका कारण क्या है ? इसका मतलब यही है कि यह सरकार चाहती नहीं है कि न्यायालयों में जल्दी न्याय लोगों को मिल सके ।

माननीय, हमारी जो नई शिक्षा नीति है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे देश में निरक्षरों की तादाद बढ़ रही है । एक नेशनल लिटरेसी मिशन है । इनकी मांग यह है कि एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1951 में हमारे देश में जहां 30 करोड़ निरक्षर की तादाद थी वहां 1981 में तकरीबन 44 करोड़ की हो गयी है और उनका अनुमान है कि सन् 2001 में हमारे देश में 50 करोड़ की संख्या हो जायेगी । उसी अनुमान के अनुसार हमारे देश की आबादी सन् 2001 में 100 करोड़ होने जा रही है । जिस देश की आबादी का आधा हिस्सा यानी 50 प्रतिशत निरक्षर होगा वह देश कैसे प्रगति कर सकता है यह बात समझ में नहीं आ रही है । कैसे इस देश में लोग शिक्षित हों, कैसे लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो, कैसे यहां के लोग नागरिक जागरूक हों इस सम्बन्ध में मेरा आरोप है कि सरकार कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठा रही है । अगर प्रभावकारी कदम उठाये गये होते या भविष्य में उठाने का इरादा होता तो इस देश की निरक्षरता की संख्या में कमी होती, परसेंट हरगिज नहीं होती, इसमें कमी होनी चाहिए थी । यह सही है कि इस देश में आबादी बढ़ रही है लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में कहीं ज्यादा निरक्षरता की संख्या, निरक्षरता की सेना बढ़ रही है ।

मैं इस बात के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो संसद है इसकी उपेक्षा और इसकी अवमानना बराबर इस देश की सरकार कर रही है । जो बजट की पवित्रता है उस पवित्रता को भी सरकार नष्ट कर रही है, भंग कर रही है । एक मानदंड है कि बजट जिस समय प्रस्तुत होगा उस समय चीजों के दाम बढ़ाये

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

जायेंगे, नये टैक्स लगाये जायेंगे, उस समय चीजों की दरों में वृद्धि की जायेगी अथवा नहीं की जायेगी । लेकिन बजट सत्र शुरू होने के तीन महीने के अंदर पहले सरकार ने कोयले के दाम बढ़ा दिये, पैट्रोल के दाम चढ़ा दिये, खाद्यान्न के दाम बढ़ा दिये, इस्पात के दाम बढ़ा दिये, अखबारी कागज के दाम बढ़ा दिये, एल्युमीनियम के दाम बढ़ा दिये और चलते-चलते जबकि बजट आज प्रस्तुत होने जा रहा है दो-चार दिन पहले ही टेलीफोन की दरों में, टेलीग्राम की दरों में, अन्तर्देशीय पत्रों की दरों में वृद्धि कर दी । इससे 549 करोड़ रुपये की डकती इस देश की जनता पर पड़ गयी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है इस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । (**समय की घंटी**) में दो प्वाइंट और कहना चाहता हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देशाई): लास्ट प्वाइंट कहिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: सिर्फ दो चीजों की ओर ही ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । यह सरकार चुनाव से भाग रही है । इसका उदाहरण स्वयं इस देश की राजधानी दिल्ली है । गत वर्ष भी दिल्ली नगर महापालिका के चुनाव नहीं कराये गये । नगर महापालिका का जो कार्यकाल था उसमें वृद्धि की गयी एक अध्यादेश के जरिये । इसी प्रकार दिल्ली में जो महानगर परिषद् है उसके कार्यकाल में भी वृद्धि की गयी । फिर इस वर्ष भी उसी अध्यादेश कि जरिये दिल्ली नगर महापालिका और महानगर परिषद् का कार्य काल बढा दिया गया । इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि इस जनता को मौका मिले कि वह अपने वोट देने के अधिकार को प्राप्त कर सके । इसी प्रकार से बहुत से उपचुनाव भी बाकी हैं लोकसभा के । करीब 12 चुनाव लोक सभा के बाकी हैं । एक इलाहाबाद की सीट खाली है, हरियाणा की दो सीटें खाली हैं, राजस्थान की सीट खाली है, बिहार की सीट खाली हो गयी है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस सिलसिले में स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए कि कब तक लोकसभा के उपचुनाव कराय जायेंगे, दिल्ली नगर महापालिका और दिल्ली महानगर परिषद् के चुनाव कब तक कराये जायेंगे । इस लोकतंत्र में जनता को अपनी राय देने से वंचित करना अलोकतांत्रिक है । इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस संबंध में स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं ।

3.00 P.M.

SHRI RAMESHWAR THAKUR (*Bihar*): Mr. Vice-Chairman, I rise to support wholeheartedly the Motion of Thanks on the President's Address moved by a senior Parliamentarian, Shri A. G. Kulkarni.

Sir, our esteemed President, Shri R. Venkataraman, in his first historic and excellent Address in 61 paragraphs has dealt with many significant aspects of our national life and international relations. It is our national duty to examine the Address in its proper perspective and deal with it, view it, with objectivity, dignity and the spirit in which the President has addressed the Members of both the Houses.

Sir, the President's Address starts with conviction and courage. It underscores the vision of India which is a land where unity and integrity are invulnerable to external threats and internal weaknesses. The President's Address draws attention to the ideals of democracy, secularism, socialism, non-alignment, social justice, science and technology, economic development, modernisation, industrialisation, religious and cultural heritage, international understanding and co-operation. The President's Address also refers to the significant achievements made by the people and the Government of India in various fields, over the years particularly, the achievements made during the current year.

Sir, a number of hon. Members on other side have been pleased to move over 200 amendments to the President's Address. A senior Member, Shri Samar Mukherjee, Leader of the Opposition, while he was speaking, vehemently criticised the Government for its utter failure on all fronts not only during the current year but the entire period of more than 40 years since Independence. Sir, in a democracy, it is the privilege of the Opposition to criticise the Government for its shortcomings and failures. However, in doing so, should we ignore completely the actual realities? Should we deliberately undermine the sincere efforts made by the millions of our people, farmers, workers, scientists, technologists, professional and people from all sections of the community and their achievements in different walks of life? Should we be ungrateful to the people and their sense of adventure, pride in their work, hard work, enterprise and the gains obtained fully supported, organised and assisted by the Government? One can appreciate that when we use red glasses, we find everything red around us. Same must be the case when we use other coloured glasses. It is a matter of concern for the democratic values that we, in our undue anxiety, criticise the other side and lose all sense of proportion and objectivity, thereby our credibility in the public eye goes down. It is nobody's case that the Government have solved all the problems and that there are no hurdles within and beyond the control of the Government. But, Sir, we are all enlightened citizens Therefore, it is unfortunate that senior leaders like Shri Samar Mukherjee have chosen to allege that nothing has been done, nothing has been achieved, during the last forty years. It is expected that senior leaders will be more objective, realistic and speak at a level where criticism is not for the sake of criticism alone but should carry a constructive message for improvement and development. It has been alleged by Samar Babu and some other leaders like Mr. N. E. Balaram, that our Five Year Plans have failed, that the performance during the First to the Sixth Five Year Plan and during the Seventh Plan—this Mid-term appraisal is over—has been completely poor and has not benefited the people and that they are capitalist Plans. But I would like to say, if we take the actual performance, facts and figures, there have been substantial achievements from First to Sixth Plan and also during the current Seventh Plan. I would like to give examples of one or two areas only. For instance in the case of foodgrains we have been able to achieve production of 150 million tonnes. Similarly, during the Seventh Plan period, although there is some reduction during the current year, 7 to 10 per cent, we are still hopeful of achieving 175 million tonnes target. This achievement has been there in spite of the fact that our population has doubled during this period of the Sixth and Seventh Five Year Plans. We are also aware that just before independence we had great Bengal famine where lakhs of people had starvation deaths in the very city of Calcutta. That was the situation from where we started and today we are not only in a position to meet our requirements but we are in a position to modestly export our foodgrains and also have comfortable stocks for our purposes, for the unforeseen contingency as we had in the current year. Apart from foodgrains the production in other areas has also gone up. Fertiliser production has increased from 55 lakh tonnes to 85 lakh tonnes. Distribution of seed has increased from 25 lakh quintals in 1970-71 to 55 lakh quintals in 1985-86. In the last year and in the current year it has further gone up. Similarly, we find in the last 15 years coal production has gone up from 76 million tonnes to 162 million tonnes and this year it will increase further. Same is the case of aluminium production and production of other goods, electricity generation, etc. I would not like to take time of the House in giving data which is well given in the 'Economic Survey'.

The current year's performance for nine months, as has been highlighted, has been increased in almost all sectors excepting the food sector. As I have already mentioned there has been an expected decrease of 7 to 10 per cent. Excepting that there has been all round

[Shri Rameshwar Thakur]

progress in spite of the fact that we had a very severe drought in almost two-third part of the country. The power generation is likely to be 10.2 per cent more. The plant load factor between April to December 1987 has averaged 55 per cent which was about 52 per cent during the corresponding period of the last year. The growth rate in other sectors has been quite explosive. Imports have gone up by 24.7 per cent during the 9 months of the current year.

Our imports have been steady at 13.5 per cent and the trade deficit during the current year is expected to be minimised to that extent. The 20-Point Programme launched by the late Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, and being vigorously pursued by the present Government under the leadership of Prime Minister Rajiv Gandhi accounts for about 30 per cent of the total component of our Plan. IRDP, NREP, RLEGP are the major components for removal of rural poverty. During the last 7 years, IRDP has assisted about 23.4 million people among the weaker sections and other backward groups. During the period April 1987 to January 1988, NREP and RLEGP generated about 471 million mandays of employment. Similar achievements have been made in the other fields —of education, health, science and technology and other areas.

It will be essential for us in the planning process to take into consideration certain factors like monsoon and other difficulties. It has to be realised that among all the developing countries, the planning process in India has been the most successful during the last six Five Year Plans and in the current Seventh Five Year Plan. If there are difficulties of slow growth, these are nothing peculiar to this country as similar difficulties are being faced by many advanced countries also. Particularly for the benefit of our great leader, Samar Babu who was good enough to criticise that nothing has been done in the Plan, I would like to quote two or three sentences from the speech of the General Secretary of the CPSU, Gorbachev, which he made on the 18th of this month to the Central Committee which is very revealing so far as Plan is concerned. It says:

> "If we look at the economic indicators of growth separately from these factors, we will see that during four Five Year Plan periods we had on increase in the absolute growth of national income. It began declining in the early '80s. This is the real picture, Comrades".

It further says.

> "Over the past three years, public revenues declined by more than 37,000 million roubles as a result of the reduced sale of alcoholic beverages. On top of that, revenues from the sale of imported products, whose purchase we were forced to limit because of shortage of foreign currency, declined by 9,000 million roubles in 1987 as compared with 1985."

Then it concludes:

> "The existing situation demands from us immense, I would say, extraordinary efforts in two directions simultaneously —in implementing radical economic reforms and in improving the current economic situation and meeting the vital needs of our population".

So this kind of problem in the economic growth and development is peculiar to all the countries—even to the very advanced countries which are very friendly to us and which we admire. So they have also these problems and a realistic picture has been given here in this speech delivered on the 18th of this month.

Then there are other areas to which Samar Babu drew our attention. He mentioned about closure of units, particularly in the jute and sugar industry. Sickness in industry has been a feature of growth of economy and change in technology. Change of technology is a very important factor. Many of our jute mills as also the sugar mills were established more than 50 years back. Naturally, there have been factors apart from the fact that there have been management failures, lack of finance and sickness has crept into these industries, including the textile industry,

The Government has taken a number of steps to remove them and to revive many of the industrial undertakings. Some of them are doing extremely well, and the NTPC is doing well. It has taken over the burden of over 100 mills which were actually failures under the private management. Many of them have been modernised. They will take time to modernise many more of them and to make them more profitable. That is essential for the Government to do. I urge very much upon the concerned hon. Ministers to look after textiles, jute and sugar to ensure that viable mills are revived as early as possible. Wherever technical changes, modernisation is necessary, that should be brought in, and we should improve the conditions of these mills as early as possible.

But, to blame the Central Government alone is not a proper answer to the situation. It is a national problem. We should see it in the national perspective. Particularly the jute mills are mosty in the State of West Bengal, we are aware. The West Bengal Government is equally responsible for their survival. What problems we have in the State are well known, including the trade union activities and other activities which are affecting these mills and their profitable working. Therefore, we should not blame a particular action in a particular way or in a particular motivated way. That does not solve the problem.

Next one is the price index and inflation. The hon. Member also quoted the price index. We are all aware that inspite of all difficulties including the difficulties of the price rise which is not only a national but an international phenomenon, India has been able to contain the price situation in a remarkable way. Inspite of so much of pressures on it, particularly in the index of the consumer price and that of the wholesale price, as you know, even during the current year it has been possible to do that. With all the drought and the additional money that had to be spent by the Government, we have been able to contain it and to bring it to the level of about 9.8 per cent which is expected to be the latest figure, whereas in the year 1979-80 it had gone up to 21 per cent. In between there have been occasions when it went up, but during the last few years we find that inspite of all the pressures it has been possible to contain it at that level. I would urge very much the Government in this regard that more attention has to be given during the coming months and in the next financial year so that the price is contained because the consumer price particularly affects the common people at large.

Mention has also been made about the railway freight and the postal charges. We quite appreciate it because there has been a substantial increase in the levies. But one thing has to be seen objectively and from an economic angle that these services are not to be only maintained we should make substantial innovation, renovation and maintain them at a proper level of efficiency and render efficient services to the people particularly in the field of communication. Also to lay new railway lines it is essential that we should be able to spent more money on the capital expenditure and modernise the existing system. Hence the additional taxes.

Then also comes the question of the increase in the pay scales of the employees who are engaged in the task, who naturally deserved the reasonable increase which has been given. On that account, if we carry on the deficit, it will not do. It will have to be brone by the community at large who gets the services. The only thing is that in levying the charges we have to see that the poorer sections of the people are not very much affected. For instance, the money order charges, we should not have increased. Small people send money orders, and not rich people who send money through bank drafts, cheques and so on. Therefore, it is necessary to see that within the limits how far we can make reductions. That should be done. It is very surprising a suggestion has been made that ours is a capitalist plan. Planning in India derives its genesis from the appointment of the National Planning Committee which was appointed in 1938 by the All India Congress Committee under the Presidentship of Shri Subhash Chandra Bose. The Na-

[Shri Rameshwar Thakur]

tional Planning Committee was headed by Pandit Jawaharlal Nehru. That Committee examined all the aspects of planning and gave very vital suggestions. It produced different studies and strategies concerning the economic development of the nation. It had laid down that the State should own and control all the basic industries, services, mineral resources, railways waterways, shipping and other public utility services and in fact all those large-scale industries which are likely to become monopolistic in character. It was not that we had said so, but our eminent leaders like Pandit Nehru, who was father of Indian Planning and who himself was its Chairman had given it to us. Yes, we had two plans—one was Bombay Plan, which was produced in the year 1944-45 by the industrialists of Bombay and another plan was prepared by Mr. M. N. Roy at the same time. It was said to be people's plan.

After independence, the nation has taken cognisance of all the aspectse of our economy, particularly the genesis of the 1938 Planning Committee. As a result we have a plan which is supposed to be one of the best plans where we had accepted the Socialist Pattern of Society as goal and the public sector undertakings having commanding role in it. At the beginning of Planning we had only 29 public sector undertakings and today we have increased the number to more than 200 units. All the key sectors and core industrial units are within the public sector. The Prime Minister has given a new direction that this not only should have a commanding position in terms of investment, but also in terms of productivity, efficiency and profitability. That is where it is a big challenge to all of us and to those also who are engaged in the great task of working in public sector undertakings. They have a responsibility to ensure that the public sector undertakings are made the pride of the nation by bringing about these further goals of productivity, efficiency and profitability.

I would like to refer to one more aspect which has been commented upon by Samar Babu. It is about socialism. They say we have no socialism as our goal. We have left Socialism. I would like to say that this is a matter which had been agreed upon by the Congress before Indenpendence. It was accepted in a formal way in 1955 at the Avadi Congress and later on was confirmed again at the Amritsar congress and also at the Bhubaneswar Congress in 1964. Since then it is a part of the constitution, it is a part of the creed of the party and the planning process. This had been adopted in the Second Plan as part of the planning process. Therefore, to say that we have given it up is not fair. Actually apart from the earlier commitments of the previous Prime Ministers—Pandit Nehru and Mrs. Gandhi—our present Prime Minister in his last year's Budget speech had said :

> "I am committed to planning for socialism in India, which fits in with our genius, but nevertheless socialism in its basic meanng of removing disparities and providing equality of opportunity. This is the yardstick by which I want to judge all policies and programmes."

A mention was made about the point whether socialism means that we should have association with advanced countries in matters of technology and training. Samar Babu was good enough to mention about the achievements of China in the field of socialism and so on. Now, I would like to quote one thing. So far as China's experience is concerned, in the field of socialism it has done extremely well, but conditions here in India are different because we have a democratic set-up. Nevertheless when we have any collaboration with Western countries, it is criticised. But I may inform the Members that the Chinese Government has invited Harvard School to open Management Training Institutions in China. They have already opened one in Peking and two more are in the process of opening elsewhere in China. So, simply criticising the Government for modernisation is not fair. Modernisation and training from wherever we get best in the world we should have it. There should be no strings attached to these programmes.

We must have our independent way of socialism and policy frame and on that basis we should do.

Before I conclude, I want to say one more thing. The Leader of the Opposition started his speech and ended his speech by saying that the present Government must resign. I am not accustomed to talk in those terms. This is not a fair way of criticising the President's Address from senior leaders. There are other friends who can speak and we have been hearing them and accustomed to hear. But a senior-most person and a man of high political stature to talk like this is a very unfair, unrealistic and undesirable. The people have given their massive mandate—the recent mandate given in Tripura has re-emphasised it and, therefore, to talk like this is not fair. We should certainly criticise the Government for its failures and also offer constructive suggestions. But to ask the elected Government to resign or to give a solgan like "Bharat Bachao" is not fair. It is not befitting on the part of such a senior Member to say it in public life. It undermines the people's efforts to reach the goal of success in various directions. Therefore, my humble suggestion is that senior Members must refrain from criticising in those terms and create a healthy democratic atmosphere.

With these words, I once again support the Motion of Thanks on the President's Address moved by my hon. friend, Shri A. G. Kulkarni.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत के सम्मुख कुछ गंभीर चुनौतियों, जिनकी ओर राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में अधिक ध्यान नहीं दिया है, आपके माध्यम से भारत सरकार के सम्मुख पेश करना चाहता हूं। भारत संसार का महानतम गरीब देश है। आजादी के इन 40 वर्षों में गांवों में और शहरों में रहने वाले लोगों की खेती और गैर कृषि पेशा लोगों की आय में निरन्तर अन्तर बढ़ता चला जा रहा है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की घोषणा के पश्चात गरीब और अमीर की आय में अन्तर बढ़ता चला जाए यह सरकार के सम्मुख एक चुनौती है। देश में कृषि उत्पादन में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है किन्तु जनसंख्या में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर कृषि उत्पादन में 1.9 प्रतिशत और जनसंख्या में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो किस प्रकार यह देश और कितने दिनों तक खाद्यान्न में आत्म निर्भर रह सकता है और अपना आर्थिक विकास कर सकता है। प्रथम योजना और द्वितीय योजना के वर्षों में इस देश में जनसंख्या में 1.9 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई है। 1961 और 1971 के दस वर्षों 2.2 प्रतिशत से वृद्धि हुई और 1971 और 1981 में 2.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जबकि 53 अरब रुपया परिवार कल्याण योजनाओं पर भारत सरकार खर्च कर रही है। लेकिन उसका समुचित लाभ देश को ही नहीं प्राप्त हो रहा है और विशेषकर के ग्रामीण अंचल तो सर्वथा अप्रभावित है। ग्रामीण अंचल में परिवार कल्याण योजनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं है। मान्यवर, इसका क्या कारण है? मेरी दृष्टि में इसका कारण नाबालिग बच्चों की शादियां है, "अवयस्क" जिन्हें कहते हैं। मान्यवर, राजस्थान में एक दिन में 40 हजार बच्चे और बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जिनकी आयु 5 से 7 वर्ष होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 90 प्रतिशत शादियां अवयस्क बालकों और बालिकाओं की, नाबालिग बच्चों और बच्चियों की होती है और बहुत शीघ्र अवयस्क अवस्था में ही उनके बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं। इससे न माताओं का विकास होता है और न ही बच्चे स्वस्थ्य होते है और इसका नतीजा होता है कि बच्चों को जल्दी, थोड़ी उमर में ही मृत्यु हो जाती है। सरकार ने 18 और 21 वर्ष की आयु 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए कानून में निर्धारित की हैं, लेकिन वह सिर्फ कागज पर ही है। फिर यह कानून बनाया किस के लिए है, अगर 40 हजार बच्चों और बच्चियों की शादी एक दिन में हो जाती है 5 और 7 वर्ष की आयु में? यह कानून क्यों बना अगर इतनी संख्या में मध्य प्रदेश उत्तरप्रदेश, और राजस्थान में अवयस्क लड़के लड़कियों की, नाबालिग बच्चों और बच्चियों की शादियां हो जाती हैं। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भारत सरकार से कि जो कानून

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बनाया है, उसका बहुत ही कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए ।

महोदय, आजकल कोई समाचार पत्र ऐसा नहीं, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध न बढ रहे हों, चाहे वह बलात्कार के अपराध हों, अभी कल परसों पड़रिया गांव में पुलिस और कुछ ठेकेदारों ने गोलियां चलाई, जिससे गांव के आदमी डर कर भाग गए, महिलाएं अंदर रह गई, दिल खोलकर निडर होकर, उनके साथ बलात्कार किया और लूट भी की। कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को ? दहेज में कितनी महिलाओं की प्रतिदिन बलि चढ़ती है ? विधवाओं का क्या हाल है। मान्यवर, हमारी बहुत है संस्कृति है, इस देश की महिलाओं के साथ ज्यादती प्रारम्भ से हुई । सरकार का इरादा है उनके साथ ज्यादती न हो, सती-प्रथा को रोकने के लिए कानून बना अभी । मैं पुनः बलपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो महिलाओं के साथ प्रतिदिन अपराध बढ रहें हैं, उन्हें कड़ाई से रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मान्यवर, मादक द्रव्य, शराब को ही लीजिए । महात्मा गांधी जी ने खुद विरोध किया शराब के खिलाफ, लेकिन आज प्रदेश सरकारें शराब से आय बढ़ाने के लिए निरन्तर दुकानो पर दुकानें खोलती चली जा रही है । सब जानते है कि शराब इंसान के चरित्र का ह्रास करती है, उसके स्वास्थ्य को खराब करती है। जब इंसान का स्वास्थ्य और चरित्र ही नहीं होगा तो खाली पैसे से कौन से देश का निर्माण होगा । इसलिए शराब और मादक द्रव्यों का सेवन जो हमारे विद्यार्थियों में बढ़ता चला जा रहा है इसे एक चुनौती समझ कर सरकार को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए । . . .

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हरियाणा में भी तो दुकानें खोल रहें हैं, हरियाणा में तो बंद करिए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : फिर मान्यवर, देश में शिक्षा संस्थाएं बढ़ी और शिक्षा का प्रचार हुआ, लेकिन आजादी के इन चालीस वर्षों में अब तक 38 फीसदी भी जनता लिटरेट नही हो सकी, पढ़ लिख नहीं सकी और मान्यवर जो लोग कुछ पढ़े भी हैं, वे बेकार घूम रहे है आज 3 करोड़ 10 लाख आदमी रोजगार के दफतरों में अपना नाम दर्ज कराए हैं और वे बेकार हैं । बेकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं । सरकार रोजगार देने की जितनी योजना बनाती है उससे कहीं अधिक बेकार हो जाते है । इसमें मुझे एक शिकायत है, हिन्दुस्तान गांवों का देश है । यहां 80 फीसदी आदमी गांवों में रहते है । बीस फीसदी लोगों को चली जाती है और 80 फीसदी लोग वंचित रह जाते हैं । यह अन्याय दूर होना चाहिए ।

मान्यवर, राष्ट्रपति महोदय का सारा अभिभाषण मैंने पढ़ा कि कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा की होगी । यह ऐसा हुआ कि उन्हें पता ही न हो कि देश में कही भ्रष्टाचार है। मैंने अपने जीवन में इस देश का और अपना नंबर एक का शत्रु भ्रष्टाचार माना है। यह भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस की ओर सरकार का ध्यान नहीं है और इसी कारण राष्ट्रपति जी ने भी अपने संबंधन में इसकी कोई चर्चा नहीं की है। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में भी भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे, को चल रहा है। मैं पूछता हूं कि कौन रोकेगा भ्रष्टाचार को ? इसी प्रकार प्रशासन में ढिलाई बढ़ती चली जा रही है । आज सही काम भी बगैर पैसों के नहीं हो पाता। रिश्वत या सिफारिश चाहिए तब सही काम होंगे । आज विकास के कार्यों में भी कितना रुपया लगता है वहां भी ठेकेदार और इंजीनियर सब खाते है । यहां दिल्ली में डी० डी० ए० ने जो मकानात बनाए है—तीन-तीन, चार चार मंजिले, उनकी नींव नहीं रखी है। इसी प्रकार से सब जगह धन का दुरुपयोग होता है ।

मान्यवर, यही हाल मिलावट का है । संसार में आज किसी भी देश में इतनी मिलावट नही है जितनी यहां है । चाहे आदमी के खाद्य पदार्थ हों, चाहे दवाई हो, चाहे कीटनाशक हो—हर चीज में मिलावट-ही-मिलावट है । सरकार

का इस विषय की ओर ध्यान नहीं है। निश्चित रूप से इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। आज जो आदमियों का स्वास्थ्य गिर रहा है और जो हार्ट अटैक्स तथा दूसरी बीमारियां होती हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण वह होती हैं।

मान्यवर, आज देश में अराजकता का क्या हाल है। किसी भी आदमी की जान और माल की सुरक्षा नहीं है। चाहे रेल में लूट लें, रास्ते में लूट लें, बसों में लूट लें, जहां-चाहें कत्ल कर दें। यह हालत है। जी० एन० एल० एफ०, त्रिपुरा और पंजाब की आज जो स्थिति है, वह बहुत ही दुखदायी है। उनकी चर्चा मैं दुबारा जब समय मिलेगा तब करूंगा। लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूं कि देश में शांति और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नही है। अराजकता मे बढ़ोतरी हुई है। महात्मा गांधी जिनकी बदौलत यह देश आजाद हुआ, उन्होंने देश की एकता के लिए अपने प्राण दिए। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी आज इस देश में रूढ़िवादिता, फंडामेंटलिज्म बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और सिख के बीच में नफरत है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। देश की एकता और अखंडता के लिए यह एक चुनौती है और इस तरफ ध्यान दिया ही जाना चाहिए।

मान्यवर, आज देश में मंहगाई किस कदर बढी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते मिल जाते हैं और किसी हद तक आपने उनकी समस्या कों हल कर दिया। लेकिन सरकारी अधिकारी-कर्मचारी तो केवल दो-तीन प्रतिशत हैं। आज की कमर तोड़ मंहगाई का पूरा देश की जनता पर कुप्रभाव पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। इसलिए मंहगाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यहां आंकड़े दिए जाते हैं कि पिछले साल इतनी थी और इस साल इतनी है, मुद्रास्फीति पिछले साल इतनी थी और इस साल इतनी है। यह मंहगाई बिना रुके बढ़ती चली जा रही है जिसने जन-जीवन को झकझोर दिया है। प्रति वर्ष राष्ट्रपति जी कहते हैं कि न्याय सस्ता और सुलभ मिलना चाहिए। मैं इस में एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि न्याय शीघ्र मिलना चाहिए। कितने केसेज पेंडिंग पड़े हैं। कितने केसेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं पिछले दस और पंद्रह वर्ष से। तो और लोगों का न्याय शीघ्र नही मिलेगा तो 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' वाली बात हो जायेगी। लोगों का किस प्रकार से भला हो सकेगा आप देखें कि न्याय कितना मंहगा हो गया है। जितना न्याय देने में विलम्ब होगा उतना ही न्याय मंहगा होता जायेगा और लोगों को उचित न्याय नहीं मिल सकेगा। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि— और आप को भी अनुभव होगा कि न्याय अब तो बिकने भी लगा है। क्या यह रोका जा सकता है ? क्या पेंडिंग केसेज की, विचाराधीन कैसेज के शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था की जा सकती है ? क्या जो न्यायाधीशों की जगहें खाली हैं उन को शीघ्र भरा जा सकता है ?

इस देश में काला धन और तस्करी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम विदेशों से कर्ज लेते हैं हिन्दुस्तान के उपर 31,919 करोड़ रुपया तो विदेशों का ऋण हैं और हिन्दुस्तान का अंदरूनी कर्ज 1,43,745 करोड़ रुपये का है। इस पर कितना ज्यादा सूद देना पड़ता है। हम कर्ज लेते हैं अपने देश के विकास के लिये और हिन्दुस्तान के पूंजीपति हिन्दुस्तान के धनाढ्य व्यक्ति, यहां के अमीर आदमी अपनी दौलत को विदेशों के बैंकों में जमा करते हैं। मैं आप के माध्यम से यह सुझाव केन्द्रीय सरकार को देना चाहता हूं कि जिन लोगों का धन विदेशों में जमा है उस के लिये कानून बनाया जाय कि उस धन को जब्त कर लिया जायेगा और उस धन को जब्त कर के इस देश के विकास के कार्यों में लगाया जायेगा।

इस देश में सार्वजनिक उपक्रम 214 हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि उन उपक्रमों से हमारे देश की योजनाओं के लिये धन आना चाहिए। लेकिन मुझे दुख

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मंत्री जी ने अपनी चिंता तो ठीक ही व्यक्त की है लेकिन गत वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष 60 करोड़ रुपया सार्वजनिक उपक्रमों में नुकसान हो गया। पिछली दफा 84 उपक्रम 214 में से लाभ में थे लेकिन इस बार केवल 78 उपक्रम लाभ में हैं। नुकसान बढता चला जा रहा है। यह बड़ी चिन्ता की बात है सरकार के सामने और जहां मुनाफा होता है जो उन में सरकारी कर्मचारी है, जो उनके मैनेजिंग डाइरेक्टर और चेयरमैन हैं वे उस को बांट लेने की कोशिश करते हैं। यह उपक्रम देश की आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिये बनाये गये थे, उपभोक्ताओं के हित के लिये बनाये गये थे, न कि सरकारी अधिकारियों और उन के कर्मचारियों के हित के लिये। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

एलेक्टोरल रिफार्म के बारे में पहले भी कहा गया था। चूंकि यह कार्य अभी नहीं हो रहा इस लिये उस की चर्चा ही बंद हो गयी। यहां मंत्री जी ने तो उत्तर दिया कि यह मामला विचाराधीन है, हम इस के बारे में सोच रहे हैं और दो या तीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी अपने विस्तृत सुझाव भेजे हर पार्टी ने अपने अपने विस्तृत सुझाव भेजे लेकिन वे सब कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक स्पोर्ट्स और गेम्स की बात है, हमारा कितना विशाल देश है। यह सही है कि हम से बड़ा चीन है, लेकिन चीन तो अफीमचियों का देश था। लेकिन जब नवें एशियन गेम्स हुए तो वे चैंपियन बन गये थे और कोरिया जो हमारे अंगूठे के बराबर है वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान और सारे संसार का हराकर चैंपियन बन गया हाकी में तो हमारा देश स्पोर्ट्स और गेम्स में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस के लिये अधिक व्यय किया जाये, इसमें अधिक रुचि ली जाये और अधिक प्रतिभावान लड़कों को इस क्षेत्र में तैयार किया जाये।

गांधी जी ने कहा था कि गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। लेकिन आज गांव उजड़ रहे हैं। दस्तकार जितने गांवों में थे वे अपनी दस्तकारी छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए भाग रहे है, यह अब एक नई समस्या शहरों के लिए पैदा हो रही है। गांवों के जो आदमी शहरों में आ रहे हैं उससे समस्या तो आपकी पैदा होगी ही क्योंकि गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप आप ने गांवों का विकास नहीं किया इसलिए इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

वनों के लिए यह प्रति वर्ष कोई न कोई नया कानून बनता है। वनों की रक्षा के लिए आप कानून बनाते है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ही न हमारे यहां कम हैं, पर उनका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। पर्यावरण के कारण जो खराबी आ रही है उससे भी सरकार चिंतित है क्योंकि जितने कारखाने बन रहे हैं, जितनी बसें चलती हैं जितना डीजल जलता है, उससे पर्यावरण भी बहुत तेजी के साथ खराब हो रहा है, सारे संसार में पर्यावरण का शिकार जितनी हिन्दुस्तान की जनता है, उतनी कोई नहीं। इसलिए इसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय, आप जानते हैं कि मैं किसान हूं। यह देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की सारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है लेकिन कृषि उत्पाद का मूल्य और कृषि आदानों का मूल्य विनिर्मित उत्पादों का मूल्य, इन तीनों में कोई समन्वय नहीं है। किसान ने जो पैदा किया उसको क्या मिला। किसान ने जिन निवेशों का प्रयोग करके अपना उत्पाद बढ़ाया, अपनी पैदावार बढ़ाई, उसके लिए इनको क्या देना पड़ा। अपनी पैदावार बेचकर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जिन वस्तुओं की उसने खरीद की उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ा, अगर इनका कोई समन्वय नहीं होगा, और नहीं है तो इससे गंभीर स्थिति पैदा होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जिसे टर्मस आफ ट्रेड कहते हैं, उनके अनुसार प्रतिवर्ष

4 साल से कृषि का विनिर्मित उत्पाद की तुलना में औसतन माइनस 13.7 था दूसरे साल वह माइनस 14 प्रतिशत हुआ फिर 17.7 और फिर 18.1 प्रतिशत खेती की पैदावार के मूल्य में घाटा हुआ । अर्थात् उसकी आवश्यकता की वस्तुओं के मुकाबले में विनिर्मित उत्पाद के मुकाबले में उसकी आमदनी घटती जा रही है । किस प्रकार से किसान पनप सकेगा किस प्रकार से वह देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधार सकेगा ।

मान्यवर इस देश की आर्थिक व्यवस्था तो प्रभावित हुई है सूखे और बाढ़ के कारण और आप कहते हैं कि राष्ट्रीय आय पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । तो किसान पर इसका कितना प्रभाव पड़ा, आप इस पर विचार करें । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस ओर आप ध्यान दें । यदि मौका मिला तो किसी अन्य अवसर पर मैं कृषि पर विस्तार से अपनी बात कहूंगा लेकिन अभी मैं इतना ही जोर देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बड़ा शांतिमय आन्दोलन मेरठ में हुआ । 25 दिन तक बिलकुल ठंडी रात्रि में जमीन में बगैर किसी ऊपर के साए यह आन्दोलन हुआ और 25 दिन तक शांति के साथ पड़े रहे । कोई भी झगड़ा नहीं हुआ । 8 किसानों की जानें वहां गई । अभी हम चार एम०पी० मुरादाबाद जिले में गए । वहां 5 आदमियों को 15 और 16 फरवरी को गोली से उड़ा दिया गया । मैंने वहां पूछा क्यों ज्यादती हुई तो हमें बताया गया कि एक आदमी को 15 तारीख को मारा गया और 16 तारीख को 4 आदमी मारे गए । वहां शिवरात्रि का मेला था । उस गांव में बड़ी तादाद में शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए लोग गए हुए थे । कुछ लड़के रास्ता रोकने के लिए सड़क पर बैठे थे, वे भी निहत्थे थे । पुलिस ने न वार्निंग दी, न लाठी चार्ज किया, न अश्रु गैस छोड़ी, एकदम गोलियों की बौछार शुरू कर दी । एक दो आदमी वहां नान-किसान मारे गए । एक हरिजन मारा गया । उनके नाम हमारे पास हैं । एक दो गैर-किसान मारे गए । जहां सड़क रोक रहे थे, उनमें कोई नहीं मारा गया बल्कि ऐट-रेंडम उन्होंने गोलियां चलाकर लोगों को घायल किया और मारा । मान्यवर इससे भी दुख की बात यह है कि जितनी दुकानें और घर थे सारे लूट ले गए । सब पुलिस और पी० ए० सी० लूट कर ले गयी । वहां एक दरगाह शरीफ है । वहां हम गये । जितने बल्ब वहां लगे थे उनको तोड़ दिया गया । कुरान शरीफ की आयतें वहां आइने पर लिखी हुयी थीं उन को उन्होंने डंडा मार कर तोड़ दिया । वहां राड्स को तोड़ दिया और पंखे खराब कर दिये और कालीन जो कीमती थे उनको उठा कर ले गये । वहां एक इंटर कालेज के प्रिंसिपल हैं और दो टीचर्स थे जिन को उन्होंने बुरी तरह से मारा । हमने पूछा कि क्या मामला था । तो उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने फायरिंग कर दी हम अन्दर आ कर बैठ गये । पीछे ही पुलिस आ गयी और उसने किवाड़े तोड़ दिये और फिर हमें पकड़ कर ले गये । प्रिंसिपल ने कहा कि मैं प्रिंसिपल हूं, लेकिन फिर भी उनको बुरी तरह से मारा गया और उन सब की बुरी हालत कर दी ।

सूखा हमारे देश में पड़ा है इस बात को ध्यान में रख कर हरियाणा की सरकार ने गरीब मजदूरों और किसानों का बड़ी तादाद में कर्ज माफ कर दिया है । यहां भी यह बात चर्चा का विषय थी कि हरियाणा की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है । अमीर आदमियों के कर्ज माफ हो जायें जो होते ही रहते हैं और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के कर्ज तो आये दिन माफ होते ही रहते हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं करता । लेकिन अगर हरियाणा में किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ हो गये तो वह बात चर्चा का विषय हो गया । उसका भी विरोध हो रहा है । यह सुन कर मुझे दुःख हुआ । और आप भी तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं जहां गन्ने की अच्छी पैदावार होती है । हरियाणा की सरकार ने 32 रुपये क्विंटल गन्ने की कीमत दी है और वहां के मुख्य मंत्री कह रहे थे कि उसके बाद भी साढ़े तीन करोड़ रुपया मिला है शुगर मिलों से हमारी सरकार को और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार 27 और 26 रुपया गन्ने का दाम किसानों को दे रही है । यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती । और ज्यादा दाम दिया जा सकता है । अगर मिल मालिक मुनाफा

[श्री बीरेन्द्र वर्मा]

कमायें तो गरीब किसानों तक भी वह पहुंचना चाहिये, मजदूरों और मेहनतकशों के पास भी वह पहुंचना चाहिये इस तरह की कोई व्यवस्था की जानी चाहिये ।

हमारी सरकारतन्त्र पर अन्धाधुंध खर्च जारी है और कहते हैं कि यह देश गरीब है । गरीब देश में अनुत्पादक खर्च, नान-प्लेन्ड एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिये । लेकिन वह खर्च बढ़ा है और आप शायद ठीक समझेंगे मेरी इस बात को कि गवर्नर तो बहुत बड़ा कस्टोडियन होता है । उनको जहां तक हो सके खर्च कम करना चाहिये । इकोनामी करनी चाहिये । खर्च में कमी करनी चाहिये । लेकिन जितना उनके लिये खर्च करने को रखा गया है उससे दस गुना ज्यादा खर्च कर दें तो इस गरीब देश को इस तरह से अमीर देशों की नकल करके कैसे सम्हाला जा सकता है । इस बात का मुझे दुख है ।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । श्री लंका और भारत सरकार का समझौता हुआ । वह हमें भी अच्छा लगा । लेकिन आज हो क्या रहा है । हिंदुस्तान का ही जूता और हिन्दुस्तान का ही सिर । वहां हम ही अपना सारा खर्च कर रहे हैं । वहां हमारे ही आदमी मर रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं तमिलियन और इस सब पर खर्च भी हम ही कर रहे हैं और वहां के नेता और वहां की पार्लियामेंट हमें ही दोषी ठहरा रही है, वहां के प्रधान मंत्री भी । और कभी कल ही पढ़ा है, हमारे जो एम्बेसेडर है, मिस्टर दीक्षित, उन्होंने कहा है कि लिट्टे और श्री लंका की सरकार में अंदरूनी बात चल रही है । तो वहां हम किसके हित मे काम कर रहे हैं । गवर्नमेंट भी हम को बुरा कह रही है और लिट्टे वाले भी हमको बरा कह रहे हैं, तमिलनाडु के आदमी भी हमको बरा कह रहे हैं । तो आखिर हम किस के हित में वहां काम कर रहे हैं । भारत सरकार को सोचना चाहिये कि किस तरह से वे ऐसा काम करें कि जिससे वहां की जनता का हित हो, देश का हित हो, देश का सम्मान विदेशों में बढ़े और हम अपने कर्त्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा कर सकें । इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है की केन्द्रीय सरकार और मेरे द्वारा दी गयी इन गम्भीर चुनौतियों की तरफ ध्यान दे कर जनता के हित में उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेगी ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Motion moved by our hon. senior Member, Shri Kulkarni, thanking the President for his Address in the joint session to both the Houses of Parliament. The President's Address highlights the economic policies, the foreign policy of the Government, internal situation in the country and trade and commerce. The President's Address is complete in all respects. It highlights the policies of the Government.

Sir, for the first time, the President has once again emphasised the need for unity and integrity of the nation. He has also reminded us that the ideals of democracy, secularism and socialism enshrined in the Constitution have to be upheld. He has referred to various other aspects such as science and technology, social justice, economic situation and other aspects. If you go through the Address, you will find that the first and foremost emphasis has been given to the economic situation, especially because our country is reeling under drought. The President has rightly taken up this issue as the first issue. The President has also referred to the grim drought situation prevailing in our country at Page No. 9 of his speech and he has clearly indicated that about 45 million hectares of land spread over 269 districts is under the grip of drought. He has also appreciated the commendable service rendered by this Government to tackle the drought situation in the country. We know fully well that our agricultural production had touched an all-time record of 151 million tonnes in 1985-86. It was 144 million tonnes in the year 1986-87 in spite of the drought situa-

tion prevailing in the country. This year, we expect 57 per cent less than the last year's target. This Government took special care to face the challenges posed by drought and this should be appreciated by the opposition Members. Surprisingly, I find that the opposition leaders are accusing this Government as if this Government has not been performing well in the agricultural sector. This Government managed the situation well to save the people of the country from drought and this has not been appreciated by the opposition. This is the kind of approach which the opposition leaders are giving to this world. The Green Revolution was introduced by our great leader, Shrimati Indira Gandhi. In spite of the severe criticism by the various political leaders, some of them even from the Congress, she said very boldly that the Green Revolution alone will save the country from the grips of starvation. We have seen the Bengal famine in which lakhs and lakhs of people died of starvation because we could not get foreign assistance. Today, Indians can say proudly that we are not going to foreign countries with a begging bowl. In spite of dificiency in the agricultural production, we had sufficient stocks and our public distribution system is able to cater to the needs of the people of this country. Not single death has occured due to starvation. This is a great achievement of the Government which the opposition leaders are not able to appreciate. I agree that in the field of oilseeds production we are below the target. The Technology Mission has been approved by the Govern-
4 P.M. ment, and whether in the rain-fed areas or in the the drought-prone areas, the Government has taken a keen interest to sae that the oilseed production is increased.

Sir, coming to the industrial sector, the country has seen the drought in the agricultural sector, and the raw materials which are required for the industrial productions are also less because of the lower growth in the agricultural sector. In spite of it, we have reached the target of more than 12 per cent of growth in the industrial field in the year 1986-87, and it is going to be more in this year also. The performance of the small-scale industries is commendable. Except in the capital goods industry, this Government has achieved the target in all other industrial sectors, whether it be medium-scale industries or small-scale industries. In the field of public sector, we have achieved in this year a profit of Rs. 1760 crores This is because of the Government's policy of giving autonomy to the public sector undertakings, and in the growth-rate plan which has been formulated by this Government, we are giving more powers to the administrators of the public sector undertakings. But we find the Opposition leaders saying that the public sector undertakings are losing or eating away the Government money. That is the accusation we hear from them. But the performance of the Government is forgotten by them for political reasons.

Sir, coming to our tackling the situation in the internal field, the hon. leader and a serior Member of the CPI(M) has said in his speech day-before-yesterday that democracy was not safe in the hands of the Congress and that it had totally compromised with the communal organisations to remain in power and encouraged fissiparous tendencies for narrow election ends. Sir, this is the observation made by the hon. Opposition leader, Shri Samar Mukherjee; Sir, I would like to submit that we have not compromised with any communal forces in this country. Let us take the GNLF agitation in West Bengal, the TNV activities in Tripura and the Punjab situation. If the Congress party compromised with the communal forces, we would not have seen Pakistan being divided from India. The great Father of the Nation,

[Shri V. Narayanasamy]

Mahatma Gandhi did not want to compromise with the communal forces and, therefore, we have given away Pakistan to the other forces. But we find today the Opposition leaders accusing the Congress party that it is compromising with the communal forces. Sir, in Punjab, we are trying to solve the problem through political means. To my mind, political solution is the only solution for solving the Punjab problem. But if the Congress party wanted to solve the problem by compromising with the communal forces, the problem would have been solved long back. But we are not compromising on communal issues with any of the organisations or any of the parties. But forgetting this, they are accusing the Congress party that it is compromising with communal forces. And this is so without understanding the vision of the Congress party and the approach of the Congress party relating to communal forces in this country. Sir, a slogan has been raised by the CPI (M) and CPI and they are organising processsions and groups to show to the world that Rajiv Gandhi Government should resign. Sir, I would like to pose two questions to them: What are the reasons for which they want the Rajiv Gandhi Government to resign? Their only blame is that there is inflation and the situation has not been controlled in this country. But, Sir, what is happening in West Bengal? Is Mr. Jyoti Basu tackling the situation in West Bengal? The GNLF agitation is going on. He seeks the Central Government's help to solve the problem. Can we say that Mr. Jyoti Basu should resign? If we say that, will he resign? What is happening to the Nayanar's Government in Kerala?

AN HON. MEMBER: What?

SHRI V. NARAYANASAMY: I will tell you. Don't worry. Sir, the Nayanar Government has become bankrupt. They approached the Reserve Bank for funds. When the Reserve Bank refused, they sought the assistance of the Prime Minister.

AN HON. MEMBER: Financial inefficiency.

SHRI V. NARAYANASAMY: I would like to remind you of one thing. Only on the intervention of the Central Government was the Nayanar Government able to get the funds. And the CPM Governments are asking Rajiv Gandhi to resign. What about the functioning of the CPM Governments in our country? They have no policies. Their only policy is to fight the Congress party and try to get into power. You have seen how they were defeated in Tripura. The people of Tripura have shown to them that elections cannot be won by force. (*Interruptions.*) Kindly hear me. Today I will give the best example of it. The West Bengal elections, the local polls has been held. Allegations have been made by the Forward Block and the R.S.P. leaders against the Government of West Bengal and Jyoti Basu. What have they said? They have said that there was rigging, booth capturing and that the elections were held in an improper way and the CPM Cadres have been used for the purpose of winning elections. What more certificate do the CPM people want in West Bangal, that the elections were not held in a free and fair manner, and you say that the Congress Party has no locus standi to remain in power. This is the kind of opposition that we have in our country.

Sir, I would like to remind the hon. Member of another certificate given by the very great CPI leader, Shri Dange. (*Interruptions*). That is your Communist leader. Are you not agreeing with the CPI? Shri Dange has said that Rajiv is the only hope for this country. He has said this in his speech.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal) Mr. Dange has been expelled by the CPI.

SHRI V. NARAYANASAMY: Whether he has been expelled or not is not the question. He was your leader.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): They will expel even Lenin.

SHRI V. NARAYANASAMY: They have completely forgotten him today. The CPM has forgotten Lenin today. But I would like to quote the veteran Communist leader, Shri S. A. Dange. He has said that the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi is the only hope for the country. Sir, what more certificate the Communist people want for the purpose of showing to the world....

SHRI SUKOMAL SEN: He is no more a Communist.

SHRI V. NARAYANASAMY:. . .that it is only the Congress Party and our leader, Shri Rajiv Gandhi alone who is competent enough to lead the nation and no other party is there in this country for the purpose of helping the poor and solving the problems of the poor.

SHRI SUKOMAL SEN: Wonderful, except. Rajiv Gandhi there is nobody else. Only you think like that.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir what about the opposition unity. The CPI and the CPM is in one group. Then in another group is the BJP. In-between is the Telugu Desam. A CPI leader has said in one of the platforms that NTR and the telugu Desam party are a liablity to the opposition unity. Will they deny that? This kind of opposition we have in our country. (*Interruptions*).

SHRI SUKOMAL SEN: Please request your leader to order a mid-term poll.

SHRI V. NARAYANASAMY: So far we do not have a consistent and constructive opposition in this country for solving the problems, the national problems which are facing this nation. I tell you that the Punjab problem can be solved by the consensus of all the political parties; by all the political parties forgetting their differences. They have to come forward and tell to the people that the communal problem will not be a hindrance for the unity in this country.

Sir regarding the foreign issues. . .

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: (Andhra Pradesh): The Punjab problem is all your creation only. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Why do you hear him?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he is interrupting me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Don't hear him.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, our foreign policy, we have adopted it from Panditji. Indiraji was following it and our Prime Minister, he is conscious of our foreign policy and he has taken all earnest steps for the purpose of keeping our country's dignity in the world arena, whether it is on the question of South African issue or on the question of Sri Lankan issue or more recently on the Afghanistan issue. Our Prime Minister has taken a consistent view because ours is a non-aligned country which is for peace, and nuclear power can be used only for peaceful purposes.

A lot of hue and cry was raised by the Opposition parties against our army going to Sri Lanka. I would like to say that Sri Lanka is a strategic point from our defence point of view, in the Indian Ocean. If certain other foreign powers are allowed to go there, that will be posing a threat to our country. Apart from that, we went there responding to the call given by Tamils living in Sri Lanka. But the situation has taken a different turn. But now, as per reports available, we understand, Prabhakaran has agreed to come to terms with the Government of India uncoditionally, for the purpose of settling the dispute between Sri Lanka and LTTE. Mother Front has also agitated and I understand that amnesty has been given by Jayewardene Government in order to settle the dispute. A lot of hue and cry was raised

[Shri V. Narayanasamy]

by the other side without understanding the gravity of the situation, as they wanted to arouse the feelings amongst Tamils living in Sri Lanka to show to the world that Indian troops in Sri Lanka with the support of Sri Lankan troops, are killing the Tamils there. But actually, our Indian troops in Sri Lanka are doing a lot of constructive work. It has been recognised by the LTTE also. Nobody can deny it. They are giving protection to Tamils living in Sri Lanka. The LTTE wanted to dominate the entire northern and eastern parts of Sri Lanka against the interests of national unity of Sri Lanka. Therefore, we had to intervene in the matter and settle the dispute. I hope the situation there will improve and the dispute will be settled so that people living in Sri Lanka, especially in the northern and eastern parts, will live in peace and happiness, because we have gone there to protect their interests.

Now, on the internal front, especially in the field of education, the Prime Minister since assuming office, has taken concrete steps in formulating policy on education; Navodaya schools have been opened throughout the country. There was a feeling that rural areas had been neglected but now Navodaya schools have been opened in rural areas accommodating 75 per cent of rural children. Apart from that, allocation of funds for the Human Resource Development Ministry is more than double compared to what it was three years back. Education system has been revitalised because it is only through education that not only illiteracy can be removed but living standard of the people can also be improved. Besides spending so much of money for education at the school level, many new colleges have been opened. Three-language formula was adopted by the Government appreciating the sentiments of people in Southern India. So, on the education front, on the economic front, in the fields of agriculture and industry and also in our foreign policy, we have been following consistently a policy which is acceptable to the people of this country, except the Opposition parties.

Hon. Member, Shri Balaramji said that President's Address was disappointing and it did not indicate any change in the Government policy. I do not know what he means by a change in the policies of the Government. We do not want to change our policy just for the sake of satisfying the Opposition. We would like to formulate our policies and implement the same for the purpose of developing the nation, not just for the sake of satisfying the Opposition.

Sir, the members, from the other side, while they were attacking the ruling party, were not particular about the errors and mistakes which might have been committed by the ruling party. They were making only general criticism. They were saying that the Government has failed in the economic field, agricultural field etc. But they have not given any concrete suggestions for the purpose of improving the situation. They have not done it. Purposely they have not done it because they do not know. When they criticise the Government, they should also suggest how the situation can be improved. But when we go through the speeches made by the three leaders from the Opposition, we find that no concrete suggestions have been made by them except accusing the ruling party.

In the end, I would say that the President is conscious of the policies adopted by this Government and he has correctly focussed on the achievements made by this Government. Therefore, Sir, I feel, we should be grateful to the President for his Address and we should convey our thanks to him since he has given a correct appraisal of the situation prevailing in the country. Thank you.

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT (Jammu and Kashmir): Sir, the Finance Minister will start his Budget Speech in the Lok Sabha at 5 p.m. I think, we should adjourn the House around 4.30 p.m. after Prof. (Mrs.) Asima Chatterjee's speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If the House so desires, I have no objection. I think, we will adjourn at 4.40 p.m. That will be all right.

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTERJEE (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for having given me the opportunity to speak on the Motion of Thanks to the President for his Address. In fact, the Address of the President is a critical analysis and review of the achievements of the country during the period 1987-88. He has also touched on foreign relations and has expressed resentment regarding the oppression of Indians in Fiji, depriving them of their rights solely on racial basis. He has also discussed several crucial problems that the country is facing and has suggested how to tackle the situation in order to maintain peace and tranquillity within the country and on its borders.

In the last part of page 1, the President has suggested several themes which, if worked out properly, would help to maintain the unity and integrity of the country. These themes include the proper application of science and technology to wipe out poverty and disease, to provide the basic needs to the common man and to have self-reliance. Modernisation has to be undertaken and new technologies are to be developed with the help of scientific knowledge and this is absolutely necessary for increasing productivity on the agriculture industry and many other fronts. This would also help in the economic growth of the country.

The President has underlined the need to restore the moral and spiritual values, which are being eroded; and this erosion is causing mistrust, tarnishing the image of India and damaging the ideals of democracy, socialism and secularism which are enshrined in the Constitution.

Sir, as eighty per cent of the population resides in rural India, our primary concern should be to provide the basic needs, namely, clothing, dwelling units, drinking water, health care, primary education, vocational education for self-employment and facilities for agricultural development with the application of modern technology and equipment. In my opinion, to fulfil these objectives, particularly, employment-generation, rural and modern technology, as far as practicable, should be taught to the rural masses, such as pissiculture, poultry, animal husbandry, beehiving, coir-making, canning of fruits and vegetables and utilisation of bio mass for fuel production. It is true that IRDP, NREP, RLEGP and various other programmes are being implemented for the rural poor. The fund provided by the Centre for the purpose is not being properly utilised. Major portion of the fund is being channelled elsewhere thereby depriving the rural poor. Strict and stern measures are to be taken to plug the loopholes and to check corruption and malpractices. If necessary, voluntary agents and Central agents should be appointed to look into the matter, to monitor and to submit reports from time to time.

Sir, it is a good thing that for the first time we have recognised talent without a degree. Open universities have started and are expected to fulfil the objective. A national core curriculum is being developed to impart an awareness of the country's heritage and a sense of national cohesion. The number of Navodaya Vidyalayas had risen to 206. An analysis of the admission tests to these schools has shown that 41 per cent of the selected children belonged to families below the poverty line. About 77 per cent came from rural areas and the percentage of the children from Scheduled Castes and Tribes was much higher than their proportion in the total population. This is a significant step in the eradication of illiteracy. However, the national core curriculum has to make the education meaningful and help the students become self-dependent. In this context it needs mention that incentives are to be given to the students from the primary section to unfold their scientific talent. This may be done by opening science hobby centres and displaying their exhibits in science exhibition which should be held once a year in urban and rural areas. If our science students are given opportunities to develop their scientific genius, the country will make a spectacular advancement in science and technology. Our scientists and technologists have already shown their proficiency in various fields. They are, in no way inferior to the foreign scientists so far as

[Prof. (Mrs.) Ashima Chatterjee]

scientific talents are concerned. The most glaring example is the successful test firing of 'Prithvi' India's practical surface to surface missile. For this unique achievement India now joins the select group of four nations, viz. USA, USSR, China and France. A considerable progress has been made in the field of space research, nuclear science, in the area of super conductivity, semi-conductors, and in electronics and engineering science. Also in the development of drugs, including traditional medicine, the scientists have made valuable contributions.

Coming to agriculture, Sir, our target to achieve the food grains production is expected to be 175 million tonnes by 2000 A.D. To achieve this objective, new technology is to be made an integral part of the drive. Realistic efforts are being initiated to unclog the cooperative credit mechanism so that after successive years of drought farmers all over the country could get working capital to move over to a high level of productivity in different agroclimatic zones by taking advantage of availability of water. This is important because development of rainfed and arid lands agriculture holds the key to eradication of rural poverty and reducing unemployment significantly. The year 1987-88 is facing crisis in the production of oilseeds and oil which constitute one of the five technological missions. The production has been hampered due to the unprecedented drought as also flood in several part of the country.

There are nine States, viz. Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Orissa, which supply 91.3 per cent of the oilseeds. These States are in the grip of severe drought. During the period under review our target was to produce 150 lakh tonnes of oilseeds but now it is only 111 lakh tonnes. Thanks to Rabi rain, for the first time in the history of Indian oilseed crops, the Rabi production during 1987-88 will be more than the Kharif crop. The deficit of 39 lakh tonnes of oilseeds will be reduced to 20 lakh tonnes. Thirty million farmers are involved in the production of oilseeds. They could have produced more, but irrigation is quite inadequate. And therefore to reach the target of 18 million tonnes of oilseeds by 1990 and 26 million tonnes by 2000 AD, more irrigation is necessary as 86 percent of the oilseeds' area remains unirrigated.

Further, coconut and oil palm plantation should be intensified, besides the existing production of the seeds of groundnut, rape seed, mustard seed, soyabean, sunflower, safflower, sesamum and niger, with inter-cropping. Farmers are to be encouraged not only with adequate irrigation facilities, but with other facilities also including supportive remunerative prices for their agricultural produce.

Productivity is to be increased with modern technology. So far as Health Policy is concerned, subsidiary health care centres, primary health care centre and subdivisional hospitals are poorly equipped. They should be properly equipped. Not only that, they must be kept under hygienic and aseptic conditions. All measures should be taken to transport patients to health care centres for treatment.

About unemployment, official figures say that there are as many as 30.5 million people seeking jobs through employment exchange in the country at the end of February, 1987. The Statewise data on jobseekers on the live registers of employment exchanges reveal that West Bengal ranks first with 43 lakh at the end of December, 1986.

Mention may also be made that after agriculture, the decentralised manufacturing sector is the largest sector of the Indian economy in terms of employment. The economists suggest that this necessitates the replacement of Mahalanobis model by the wage goods model in the interest of growth, larger employment, better regional dispersal and avoidance of balance of payment. This may be helpful but may not entirely solve the problem due to the acute purchasing power which is actually creating difficulty in the implementation of the suggestion made.

Then about women emancipation, I must mention that women are suffering like anything their status has not improved much.

India by 2000 AD should not aim at imparting of literacy along. It should aim at emancipation and empowerment of women. There should be proper coordination, coopertaion and an unrelenting fight for women's literacy and we should inform three levels at which women's organisations function—the village, the State and national levels. These are our problems; so I am mentioning these specifically. Working women even today do not receive justice so far as remuneration and other facilities are concerned.

I am now going to conclude by saying that our development programme has suffered a set-back because a large portion of the revenue is being diverted for defence. In fact, last year the Government spent Rs. 12,500 crores on defence because of the fact that large components of our sophisticated machinery had to be imported. But now more funds are being diverted for defence in order to control the turmoil within the country and also in Sri Lanka and also to maintain law and order, security, peace and tranquility in the country itself, including the border areas.

As there is no time, I would conclude by appealing to all the parties to cooperate, to get united and to work together for better India and to save the country from total disintegration.

Thank you.

श्री राम चंद्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जैसी सदन की इच्छा है कि यह बजट के लिये चर्चा बंद की जाये। तो मैं शुभारम्भ करूं या कल इस पर बोलूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप शुरू कीजिए।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव हमारे योग्या साथी कुलकर्णी जी ने रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही राष्ट्रपति जी ने अन्दर और बाहर की जिन चुनौतियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और हमारे देश की प्रगति में जो चीजें बाधक हैं और जो हमारी उपलब्धिया है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गयी है। उस सबक साथ में स्वयं को संबद्ध करता हूं और उनका समर्थन करता हूं। लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से जो कुछ सुझाव और शिकायत आई है, उनके बारे मे, मुझे कुछ कहना है। श्री समर मुखर्जी जो हमारे लीडर आफ द अपोजीशन हैं, हमारे साथ लोक सभा मे भी रहे हैं, बहुत दूरंदेशी और मंजे हुए नेता हैं। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री की विदेश नीति का समर्थन किया है, अन्य विधेयकों का समर्थन किया और इसके बावजूद यह कहा कि सरकार जल्दी चुनाव कराये और इस्तीफा दे। इसमें कुछ तारतम्य मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी ज्यादा समर्थन करते हुये भी आप कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी त्यागपत्र देकर चुनाव करायें। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्य जानते हैं और विरोधी पक्ष के अनेक नेताओं की आज यह भावना है कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। क्या इस विकल्प की भूमिका में विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बारे में चिंतन किया है। मैं बहुत छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं कि अगर वह देश और प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प चाहते हैं तो वह अपनी शेडो गवर्नमेंट बनाकर दिखाएं जिससे कि देश की जनता को यह आशा बंधे कि इनके बाद इस देश को चलाने के लिये कौन आएगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, ढाई वर्ष के जनता राज का अनुभव इस देश की जनता को, हमको और विपक्ष को भी है। वह जनता पार्टी का राज चाहे लोगों की नाराजगी से हुआ हो या हमारी कमजोरियों से हुआ हो, बिना कांग्रेस पार्टी की किसी कोशिश के, आपस के मतभेदों की वजह से ही वह सरकार स्वयं चली गयी गद्दी छोड़कर। मैं पूछना चाहता हूं कि वे किस मुंह से यह आशा करते हैं कि हम कांग्रेस का विकल्प जल्दी बन सकेंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी दिल्ली के बारे में मालवीय जी शिकायत कर रहे थे दिल्ली के चुनाव नहीं कराये। गृह मंत्री जी

[श्री रामचन्द्र विकल]

ने कई बार स्पष्टीकरण दिया है कि दिल्ली के ढांचे को बदलने का विचार होगा जिसकी मांग भी कई बार की गयी है कि दिल्ली की जनता विधान सभा चाहती है। तो उसके लिये कमटी और मामले विचाराधीन हैं तब भी इन सवालों को बार-बार इस तरह से उठाना उचित नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी हमारे वर्मा जी बहुत शिकायत कर रहे थे कि अपराधों में बहुत वृद्धि हुई है। वर्मा जी जानते हैं कि अपराध के मामलों में सरकार के साथ-साथ पहले समाज और भगवान का भी लोगों के दिलों में भय था। लोगों की अब समाज में और भगवान में आस्था नहीं रही। आज की डेमोक्रेसी में सरकार का भय तो धीरे-धीरे पब्लिक के मन से कम हो रहा है। अपोजीशन के लोग भी कुछ भावनायें पदा करते हैं जिससे कि सरकार का भय कम हो रहा है। मैं पूछता हूं कि ये हड़ताल और बंद क्या देश के विकास में सहायक हैं। इन बातों पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये। जब देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हों तब हमारे विपक्ष के लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी आती है। बंद किस लिये होते हैं, हड़तालें किस लिये होती हैं? क्या ये देश के विकास में सहायक हैं? ये कुछ राजनीतिक लोगों की राजनीतिक महात्वाकांक्षा बढ़ाने के आलवा या कुछ नाराज लोगों की नाराजगी बढ़ाने के अलावा आग में घी का काम भी करते हैं। हमारे लिये राष्ट्र हित सर्वोपरि है और पक्ष-विपक्ष के सामने देश की तस्वीर है, ऐसे में विपक्ष की भूमिका कुछ अच्छी नजर नहीं आती। हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार हैं रात-दिन मानते हैं और उसके लिये पश्चाताप करते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष के लोग भी इन मामलों में कुछ सजग और सावधान हों।

उपसभाध्यक्ष जी मै किसानों की बहुत सी बातों में वर्मा जी से सहमत रहता हूं। मैं अन्य बातें आज न उठाते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि राजधानी क्षेत्र के किसानो की समस्यायें बहुत जटिल हो चुकी है। यह भूमि अधिग्रहण का कानून ऐसा है जिसमें तुरन्त संशोधन होना चाहिये राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कानून हैं। दिल्ली में कुछ है, हरियाणा में कुछ है और यू० पी० में कुछ है और यू०पी० में जी०डी० ए० में कुछ है और नोएडा में कुछ है। तो यह सारे कानून समान होने चाहिये भमि अधिग्रहण के देशव्यापी पैमाने पर। नहीं तो इन से किसान त्रस्त होता है। उस का मुआवजा तय नहीं हो पाता। होता है तो समय पर नहीं मिलता और फिर उसके लिये दोषपूर्ण नीतियां हैं कि जिनके कारण मुआवजा किसान को समय पर नहीं मिलता। जमीन के अधिग्रहण के बाद में जो लोगों की आवास व्यवस्था होती है उसमें बहुत ज्यादा खराबियां नजर आती हैं। तो इस तरह की नीतियों पर फिर विचार हो कर उन में सुधार होना चाहिये। अधिकारियों की अनेक बातें मैं नहीं कहूंगा, न कहना उचित ही समझता हू, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वे सरकारी अधिकारी होते हुये भी व्यापारी बन गये हैं और एक तरह से कालोनाइजर्स से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे उदाहरण मैं देने के लिये तैयार हूं हमको इसके लिये एक बोर्ड बनाना चाहिये कि जिसमें जन प्रतिनिधि हों और उनकी देखभाल में हमारे क्षेत्र में विकास का और भूमि अधिग्रहण का काम हो और किसानों को जो मुआवजा देने का काम है वह हो और उसकी दरों को तय किये जाने का काम हो। इसके लिये आवश्यक तौर पर एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में अन्य भी बहुत से सुझाव है जिनको मैं यथा-समय दंगा।

सांप्रदायिकता के मामले में सभी लोग चिंतित हैं चाहे वे यहां पक्ष में हों या विपक्ष में और इस मामले में कहना चाहता हूं कि बाहरी शक्तियां हमको खराब नहीं कर सकतीं अगर अन्दर से हम सब लोग एक हों। अगर हमारे अन्दर कोई फूट न हो। राष्ट्रीय मामलों पर विदेशी चाहे जितना सिखायें, विदेशी चाहे जितने हथियार समुद्र पार से पाकिस्तान को भेजते रहें चाहे समुद्री बन्दरगाहों पर कितनी ही अमरीकी सेनायें जमा हो जायें, हमारे देश को बाहर के दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है अगर हम सब में सद्भावना हो, अगर हम सब एक हों। चाहे धार्मिक लोग हों या राजनेता हों, हमको चाहिये कि इन सारे सवालों को हम सब आपस में मिल

कर तय करें और अपनी शक्ति को अनुपयोगी कामों में खर्च न करें। हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि जब भी कोई बाहर की चुनौती आती है तो वह एक दीवार की तरह से उसके सामने मिल कर खड़ी हो जाती है और धार्मिक और सांप्रदायिक मत-भेदों से वह ऊपर उठ जाती है। इन मत-भेदों को बढ़ाने की कोई कोशिश अगर हमारे धार्मिक और राजनेता न करें और उनके लिये सक्रिय हिस्सा न लें तो देश एक ही रहेगा। हमारा देश समृद्धिशाली है और देश आगे भी बढ़ रहा है।

बिजली के मामले में आये दिन बात होती है और आज भी एक सवाल के दौरान बड़ी शिकायत थी। हमारी बिजली की पैदावार बढ़ रही है और उसका उपयोग भी बढ़ रहा है। लेकिन आप भी यह जानते हैं कि उसका दुरूपयोग भी जरूरत से ज्यादा हो रहा है। किसी राष्ट्र को जब बनाना होता है तो जो सब से जरूरी चीज होती है उसका दुरुपयोग नही किया जाना चाहिये। आज शादियों में बिजली का बहुत दुरुपयोग होता है। सूखे के समय में इसको रोका जाना चाहिये। आज गांवों में सुबह बारात जाकर शाम को वापस आ जाती है। इससे बिजली और बिस्तरे का खर्च बच जाता है। तो सरकार को भी समाज के साथ इसकी बचत के लिये एक्शन लेना चाहिये। और बारातों पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिये। इससे बिजली बचायी जा सकती है और जहां सूखा और अकाल पड़ रहा है वहां आज हाथ सुखाने के लिये भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। बजाय तौलिये या रुमाल से हाथ सुखाया जाये, बिजली का इस्तेमाल कर के हाथ सुखाया जाता है। यह बिजली का बहुत बड़ा दुरूपयोग है। और सरकारी दफ्तरों में भी मैंने कई बार देखा है कि छुट्टी के दिन भी पंखे चलते रहते हैं। तो यह हमारे देश का राष्ट्रीय चरित्र हो गया है। तो चाहे राष्ट्रीय ने हों या समाज सुधारक हों, जब देश संकट है तो हमें उस को समझना पड़ेगा

श्रीमन्, भ्रष्टाचार की बात तो प्रा हुआ करती है। इसके बारे में मैं कह चाहूंगा कि . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई अब आप कल अपना भाषण कीजिए।

Now, the House stands adjourned will meet again today at 7.00 P.M.

The House then adjourne forty-one minutes past four the clock.

The House reassembled at four minutes past seven of the clock, **Deputy Chairman** in the Chair.

THE BUDGET (GENERAL), 1988

THE MINISTER OF FINANCE A THE MNISTER OF COMMERCE (S NARAYAN DATT TIWARI): Ma Deputy Chairman, I beg to lay on Table a statement (in English and Hi of the estimated receipts and expendi **of the Government of India for the** morrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now House stands adjourned till 11 A.M. morrow.

The House then adjourned sixteen minutes past seven o clock till eleven of the cloc Tuesday, the 1st March, 19

MGIPMRND—L—1975 RS—3-6-88—400.